हुए भी यदि कोई मंत्री अंग्रेजी की कापी दें तो हिन्दी की कापी देना आवश्यक है, आप रूलिंग दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

DR. V. MAITREYAN: Where is the English copy, Sir? ...*(Interruptions)*... Sir, give us the English copy. ...*(Interruptions)*... Where is the English copy? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The English copies will be distributed as soon as the Minister starts reading the statement. ...*(Interruptions)*...

**श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** माननीय उपसभापति महोदय, हमारे विद्वान मंत्री महोदय ने 407 को जो पढ़कर सुनाया, मैं कहना चाहता हूं कि यह क्वेशचंस के बारे में है।

**श्री सुरेश पचौरी:** No, No, आप नीचे पढ़िए।

**श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। साइमलटेनियस इंटरप्रिटेशन की सर्विसिज़, चाहे जो भी available हो, किंतु पिछले शुक्रवार को यह ईशू यहां पे उठा और उस वक्त से गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय जो राजभाषा का कस्टोडियन है, पूरे भारत में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसे लागू करता है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** अहलुवालिया जी, यह ठीक है, मैं मानता हूं। आपकी बात से ...(**व्यवधान**)...

**श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** और उत्तर प्रदेश से जिस व्यक्ति ने नोटिस दिया है, उसको अंग्रेजी नहीं आती ...(**व्यवधान**)... यह स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को पेश करके ...(**व्यवधान**)... हिन्दी की कापी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** आ गई है, कापी आ गई है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** हिन्दी की दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, Ruling 407 says that... ...*(Interruptions)*... ...therefore, Hindi copy is not required. That is the ruling given by the Chair. ...*(Interruptions)*...

**श्री रूद्रनारायण पाणि:** उपसभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** आप बैठिए, आप बैठिए न। ...(**व्यवधान**)... आप unnecessary क्यों बात उठा रहे हैं। आपको हिन्दी की ही देंगे। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए न। बैठिए। Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

---

## STATEMENT BY MINISTER—Contd.

**The Serial Bomb Blasts in Uttar Pradesh on 23rd November, 2007.**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise, with a deep sense of anguish, to inform this august House of the tragic incidents of terrorist violence that ocurred in the court premises in Varanasi, Faizabad and Lucknow on 23.11.2007.

As per the latest information, five bomb blasts took place in these three cities within a span of about 20 minutes.

There were two blasts in the Varanasi court premises in which 9 persons including three lawyers and one twelve year old boy have been killed and 56 others injured. Out of the injured, 2 persons are reported to be critical. I along with officials of the Ministry of Home Affairs visited the blast sites in the Varanasi Court premises and the injured admitted in Deen Dayal Upadhyay Hospital, Singh Nursing Home and BHU Hospital. In the Court premises in Faizabad, there were 2 blasts in which 4 persons have lost their lives including one advocate and 24 persons have been injured. In Lucknow, there was one bomb blast but it did not cause any loss of life or injury.

The *modus operandi* adopted in these blasts was that the explosives with a battery operated timer device were contained in a bag and kept on the bicycles parked close to the area where lawyers/litigants sit. The teams of NSG personnel have visited the blast sites for post-blast investigations.

The investigations into these blasts have been given to the Special Task Force (STF) by the State Government. The Central agencies are also helping the State Police in this regard. The State Government, as per the latest reports, has annoucned compensation of Rs. 5 lakhs to the next of kin of those deceased and Rs. 1 lakh for those seriously injured.

The Uttar Pradesh Government has also given directions to enhance and strengthen the security of all district courts and especially of the Allahabad High Court and the Bench of the Allahabad High Court in Lucknow. The State Government has also increased vigil at sensitive and crowded places, educational institutions, etc.

KUMAR DEEPAK DAS (Assam): Sir, about Assam blasts, there is no statement! *(Interruptions)*

**श्री उपसभापति:** आप बैठिए ...(व्यवधान)... पूरा पढ़ने तो दीजिए, अभी आप बैठिए ...(व्यवधान)... आप मिनिस्टर को पढ़ने दीजिए। अभी, आप बैठिए, आप बाद में बोलिएगा ...(व्यवधान)... Let him complete.

SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL: The Government strongly condemns these incidents of mindless terrorist violence, and reiterates its firm resolve to combat terrorism. The security and intelligence agencies continue to make sustained efforts to neutralize such extremist and terrorist elements through preventive measures.

The fight against terrorism has to be fought at different levels. Besides the Government, political parties, civil society, media and the public at large, all have to play an important role in countering such forces. We will not allow these anti-national forces to disturb peace and communal harmony in the country.

We mourn the loss of invaluable lives of innocent citizens and convey our heart-felt condolences to the affected families.

**श्री उपसभापति:** अच्छा, आसाम का इसमें included नहीं है ...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, there is already a feeling of neglect in the North-East. A small paragraph could have been included in this statement also.

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:** अगर आपका आदेश हो, तो शाम को आसाम पर भी स्टेटमेंट दे दिया जाएगा।

**श्री उपसभापति:** ठीक है, जोशी जी, आप बोलिए।

**डा० मुरली मनोहर जोशी** (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसले पर बोलने का अवसर दिया है। मुझे इस बात की चिंता है कि ऐसे गंभीर मामलों पर सरकार की ओर से जितनी गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी, उसमें कुछ कमी रह गई है। आज मेरा उद्देश्य आलोचना करने का या शिकायतें करने का नहीं है, लेकिन इस मसले पर गंभीरता जरूर होनी चाहिए और इसमें बहुत अधिक गंभीरता की जरूरत है, मैं इसकी तरफ जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे इस पर भी अफसोस है कि जो घटनाएं वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ में हुईं, सदन उस दिन चल रहा था, लेकिन सरकार की ओर से पहले जानकारी टेलीविजन पर दी गई और सदन में बाद में दी गई। अगर यह बात सच है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, तो यह एक तरह से शिष्टाचार के विरुद्ध है, हमारी परम्पराओं के विरुद्ध है और चलते हुए सदन के दौरान, सदन से बाहर पहले जानकारी देना किसी ही हालत में उचित नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा भी जैसा आज सुबह हमने दृश्य देखा,

उससे लगता है कि जितनी गंभीरता इस वक्तव्य में कही जा रही है, यह आचरण में दिखाई नहीं देती। उपसभापति जी, मैं उन स्थानों पर गया था और वहां मृतकों के परिवारों और घायलों से मैंने प्रत्यक्ष रूप से विचार किया और देखा। एक बात जो सामने आई, वह यह है कि तीनों घटनाएं कचहरी के परिसर में हुई है और यह केवल संयोग ही नहीं है कि उस दिन हुई है जब कि वाराणसी के न्यायालय में एक आतंकवादी मुकदमे के मामले में एक व्यक्ति की, एम०एल०ए० की विधायक की गवाही थीं और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि उस विधायक को सरकार के द्वारा जो सुरक्षा प्रदान की गई थी, वह हटा दी गई और उनके जीवन को उस दिन बहुत खतरा था। वाराणसी में जहां यह विस्फोट हुआ उसके पास जो दीवाल थी अगर वह दीवाल थोड़ी सी पतली होती तो निश्चित रूप से यह विस्फोट उस विधायक के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। इससे यह अंदाज लगता है कि इम मामलों में जितनी गंभीरता बरती जानी चाहिए थी, उतनी प्रदेश की प्रशासन के द्वारा नहीं बरती गई। हो सकता है कि यह अचानक हुआ हो, गैर-जानकारी में हुआ हो, लेकिन अगर यह एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत सबकी सुरक्षा घटाने के सिलसिले में कर दिया है तो यह बहुत गंभीर बात है और मैं समझता हूं कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह इस बात को दिखाता है कि वाराणसी में जितनी गंभीरता से मामलों को लिया जाना चाहिए था, हमने नहीं लिया। इसी तरह से, लखनऊ में वकीलों पर आक्रमण हुआ, वाराणसी में भी वकीलों पर आक्रमण हुआ और लखनऊ में उन वकीलों की बहुतायत थी, बहुत संख्या थी जिन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे लेने से इंकार कर दिया और एक तरह से यह उनका फैसला है कि हम आतंकवादियों के मुकदमे नहीं लेंगे, इससे नाराज होकर और उनको डराने के लिए, उनको भयभीत करने के लिए आप हमारे मुकदमें क्यों नहीं लेंगे, उनको आतंकित किया जा रहा है और अगर आप हमाने खिलाफ काम करेंगे तो आपको काम करने नहीं दिया जाएगा। लखनऊ में आतंकवाद का यह एक दूसरा पहलू है। फैजाबाद में भी राम जन्म भूमि पर हुए मामले में मुकदमा चल रहा है, तो यह साफ दिखाई देता है कि आतंकवादी कार्यवाहियों के विरुद्ध जब अधिवक्तागण आते हैं, वकील आकर खड़े होते हैं तो उनको terrorise किया जाए, उनको डराया जाए, उनको काम न करने दिया जाए, यह इसमें से एक चित्र उभर कर आता है। इसमें से एक बात और उभरती है कि न्यायपालिका का जो प्रमुख अंग है न्यायाधीश, उसको भी terrorise किया जाता है कि वे अगर इस तरह के काम करेंगे तो फिर उनके ऊपर भी हमले होंगे। उन्हें याद दिलाया जाता है कि एक न्यायाधीश ने किसी आतंकवादी को फांसी की सजा दी थी तो वह न्यायाधीश मौत के घाट उतार दिए गए थे। इस आतंकवाद का यह जो पहलू आया है कि अगर आतंकवादी पकड़ा जाए, अगर आतंकवादियों के खिलाफ गवाहिया मिलने लगें तो वह कार्रवाई न होने दें, यानि एक तरफ आतंकवाद करो और फिर अगर यहां कोई कार्रवाई की जाए तो फिर उसको भी विफल करो, यह एक ऐसा पहलू है जिसकी तरफ मैं समझता हूं कि सदन को गहराई से ध्यान देने की जरूरत है, राज्य सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है और केन्द्र सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। फिर दूसरी बात यह कही जा रही है कि Intelligence Agency क्या कर रही है? अब एक बहस यह है कि केन्द्र सरकार कहती है कि हमने राज्य सरकार को सारी सूचनाएं दी थीं, राज्य सरकार कहती है कि हमें कोई सूचना नहीं मिली। अब अगर राज्य और केन्द्र के बीच में यह हालत है तो भगवान देश का भला करे, फिर तो हम आतंकवाद से नहीं लड़ सकते हैं। आज तक यह क्यों नहीं हो पा रहा है कि राज्यों और केन्द्र के बीच में बराबर तालमेल बना रहे, सूचनाओं का आदान-प्रदान ठीक समय पर हो। अगर राज्य सरकार के पास सूचना आई है तो कब आई है? मैं जानना चाहूंगा गृह मंत्री जी से कि इस प्रकरण में सूचना केन्द्र सरकार के पास कब आई, किस स्तर पर आई, क्या सूचना आई और उन्होंने राज्य सरकार को वह सूचना कब भेजी, किस स्तर पर भेजी? राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी यहां बैठे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि वह यह बतएं कि उन्हें सूचना मिली या नहीं मिली और अगर मिली तो उन्होंने क्या काम किया और नहीं मिली तो उसके बारे में स्पष्टीकरण दें?

**श्री उपसभापति:** राज्य सरकार के प्रतिनिधि यहां नहीं बोल सकते हैं, Members of Parliament बोल सकते हैं।

**डा० मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश):** वह बैठे हैं, मेम्बर्स की हैसियत से ही मैंने बोला है।

**श्री उपसभापति:** वह यहां पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं।

**श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश):** वह Advisory Council के member हैं और कैबिनेट मंत्री का दर्जा है।

**श्री उपसभापति:** वह यूपी में है, यहां पर Hon'ble Member हैं।

**डा० मुरली मनोहर जोशी** (उत्तर प्रदेश): सर, वह भी हैं और यह भी हैं। यहां पर Hon'ble Member की हैसियत से बोलेंगे और चूंकि जानकारी उस हैसियत से उनके पास होगी। मैं ऐसा समझता हूं, इसलिए बराबर हमारा अनुरोध है कि इस मामले में बात साफ होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश में बराबर आतंकवाद हो रहा है और आज तक यह स्थिति नहीं बन पाई कि राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच में सूचना तंत्रों का किसी प्रकार का ठीक से संबंध हो, जानकारी हो और अगर पहले से जानकारी थी, तो फिर राज्य सरकार का यह घोर अपराध माना जाएगा कि उन्होंने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की और अगर केन्द्र सरकार ने सूचना नहीं दी थी, तो श्रीमन्, फिर इसके बारे में यह माना जाएगा कि केन्द्र सरकार भी इस मामले में गफलत में थी और उसको बहुत कैजुअली लेती।

महोदय, एक बात इससे और सामने आती है कि अभी पिछले दिनों कुछ लोग पकड़े गए और उन्होंने कुछ बयान दिए। वे बयान क्या दिए थे, कब दिए थे, क्या उन बयानों को राज्य सरकार ने देखा था, केन्द्र सरकार ने देखा था? उसके आधार पर क्या सूचनाएं मिलीं? पिछले दिनों कुछ अपराधी पकड़े गए और मुस्तैदी से पकड़े गए। तो अभी क्या हो गया है कि एक कांड में तो आप मुस्तैदी से पकड़ लेते हैं और बाकी कांडों में आप सूचना-तंत्र के बारे में इधर-उधर के बयान देते हैं। यह गोरखधंधा मेरी समझ में नहीं आता है। चार दिन पहले तो आप तीन आतंकवादी पकड़ लेते हैं, घोर अपराध करने वालों को पकड़ लेते हैं और चार दिन बाद आपके सूचना-तंत्र के तार कट जाते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा ध्यान कितनी गंभीरता से आतंकवाद की तरफ है?

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह स्वीकार किया था कि लगभग पैंतीस जनपद ऐसे हैं, जहां आतंकवादियों के अड्डे हैं और अभी पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि देश में 45 ऐसे प्रमुख अड्डे हैं, जहां आतंकवादियों ने अपने गढ़ बनाए हैं, उसमें से 10 अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में इन आतंकवादियों के गढ़, अड्डे सुदूर गांवों में भी पाए गए हैं। महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** हां, क्योंकि यह क्लैरिफिकेशन ही है। When we discuss internal security we can talk about it.

**डा० मुरली मनोहर जोशी** (उत्तर प्रदेश): जी हां, लेकिन internal security ही हालत कितनी खराब है, वह इसका प्रदर्शन करती है। तराई के सारे जिलों में, इसी तरह पश्चिमी यू.पी. के जिलों में और जिस जिले में मैं रहता हूं, वहां आतंकवादियों के अड्डे देहात में आए हैं और हालत यह हो गई है कि उसमें से जो आतंकवादी बनारस के बम विस्फोट में जिम्मेदार पाया गया था, जब उसके खिलाफ गवाही आनी शुरू हुई, तो सरकारी वकील ने बोलने से इंकार कर दिया और वे कुछ नहीं बोले और श्री वली उल्लाह को एक्स-पार्टी रिलीफ मिल गई। यह क्या है? यह क्या आतंकवाद से लड़ने की हमारी मनोवृत्ति को दिखाता है? क्या हम गंभीर हैं इस मामले में? क्या सरकार और सरकारी वकील डरे हुए हैं? क्या कोई और फोर्सेज काम कर रही हैं? हम आतंकवाद से कैसे लड़ेंगे? गृह मंत्री जी का बयान है कि all levels, civil societies, State Governments, Central Government सब मिलकर लड़ेंगे। कहां लड़ेंगे? किधर लड़ेंगे? ऐसे लड़ेंगे? अदालत में बयान नहीं देंगे? सूचना तंत्र को बिल्कुल खोखला करके रखेंगे और आपस में कोई तालमेल नहीं रखेंगे और प्रस्ताव में हम बहुत बहादुरी से लड़ेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस सारे ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** जोशी जी, जरा जल्दी समाप्त कीजिए। बहुत सारे मैम्बर्स ने बोलना है।

**डा० मुरली मनोहर जोशी:** जी हां,? बहुत से मैम्बर्स बोलेंगे, केवल एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। जो अभी तक का एक चित्र उभर रहा है, मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं कि एक बार हमारी सम्प्रभुता पर हमला होता है, सदन पर हमला होता है, फिर हमारी आर्थिक राजधानी पर हमला होता है, फिर हमारे वैज्ञानिक केन्द्र-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर पर हमला होता है, उसके बाद हमारे जो धार्मिक और सांस्कृतिक केन्द्र हैं, उन पर हमला होता है और होते-होते हैदराबाद में मस्जिद के पास और अजमेर शरीफ पर हमला होता है, यानी जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन पर हमला होता है। अब हमारी न्यायपालिका और वकीलों पर हमला होता है और श्रीमन्, मुझे आशंका है कि अगला हमला प्रेस पर होगा। जिस ढंग से तसलीमा नसरीन के मामले को उठाया गया है, हालांकि वह यू.पी. से सीधा संबंधित नहीं है, लेकिन इस व्यापक आतंकवाद से संबंधित है। हम उसको प्रोटैक्शन नहीं दे सकते। कुछ लोग, फंडामेंटलिस्ट

1.00 P.M.

उठकर कुछ कहना शुरू कर देते हैं और सरकार दुम दबाकर भाग जाती है। क्या आप आतंकवाद में ऐसे लड़ेंगे? ये कौन तत्व हैं, जो इस तरह की आवाज उठा रहे हैं? यह फंडामेंटलिस्ट्स कहां से आ गए? किस तरह से एक आंदोलन को आप फंडामेंटलिज्म के साथ जोड़ रहे हैं?

**श्री उपसभापति:** नहीं, यह wider issue है आप इसके साथ ...(**व्यवधान**)...

**डा॰ मुरली मनोहर जोशी:** पर मैं आपको बता रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** क्योंकि यह डिसकशन स्टेटमेंट पर है, on wider issues we can discuss separately.

**डा॰ मुरली मनोहर जोशी:** जी हां, बिल्कुल, लेकिन मैं सिर्फ प्वाइंट आउट कर रहा हूं कि ...(**व्यवधान**)...

**श्री शाहिद सिद्दिकी** (उत्तर प्रदेश): आप 18 करोड़ मुसलमानों का दिल दुखाएंगे, तो ...(**व्यवधान**)...

†[**شری شاہد صدیقی :** آپ 18 کروڑ مسلمانوں کا دل دکھائیں گے، تو ۔مداخلت۔]

**श्री उपसभापति:** नहीं, नहीं, देखिए, यह wider issue है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, नहीं तो अभी फोकस इसके ऊपर चला जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

**डा॰ मुरली मनोहर जोशी:** मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... किसी मुसलमान का दिल मैंने आज तक नहीं दुखाया है और दुखाने की कोशिश भी नहीं है, लेकिन हिन्दुस्तान का जो कंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जिसमें हमें इन चीजों को, इन मूल्यों को प्रोटेक्ट करना है। अगर हम उन मूल्यों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और आतंकवाद के सामने सरेंडर करते जाएंगे तो हम आतंकवाद से नहीं लड़ सकेंगे। इसके अलावा आखिर में मुझे जो कहना है वह यह है कि अब इंडियन टेररिस्ट नाम से नए आउटफिट्स को जन्म दिया जा रहा है। हूजी ने अपने नाम के साथ अब इंडियन टेररिज्म जोड़ दिया- यानि अब तक आतंकवाद बाहर से आ रहा था लेकिन अब हालत यह हो गई है कि यह कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के अलावा राष्ट्रीय आतंकवाद भी पैदा हो रहा है जो बहुत खतरनाक है। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भाई यहां संसद में बैठे हैं, वे इसका डटकर विरोध करें और वे साफ बताएं कि भारतीय आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है। भारत में भारतीय टैररिस्ट्स आउटफिट्स पैदा हो रहे हैं, यह एक बहुत खतरनाक बात है।

**श्री उपसभापति:** जोशी जी, जरा कनक्लूड कीजिए।

**डा॰ मुरली मनोहर जोशी:** यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यह नहीं होने देना चाहिए। सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर आतंकवाद से लड़ना है तो सरकार की पॉलिसी इस मामले में क्या है? क्या सरकार पोटा कानून लाएगी? क्या सरकार सिक्योरिटी एजेंसीज को अपग्रेड करेगी? क्या सरकार को न्युक्लियर टेररिज्म के खतरे मालूम हैं? क्या सरकार के सुरक्षा बलों का, और खास तौर पर जो इन कामों के लिए डिप्यूटेड फोर्सिज हैं, उनका मनोबल ठीक है, क्या उनकी सुविधाएं ठीक हैं, क्या उन्हें बराबर ट्रेनिंग देकर अपग्रेड कर रहे हैं? क्या ट्रॉमा सेंटर्स जगह-जगह पर हैं? इस सारी घटना में मैंने देखा कि एक ट्रॉमा सेंटर सिर्फ लखनऊ में है, सारे पेशेंट्स वहां जाएंगे। आप आतंकवाद से किस स्केल पर लड़ेंगे? सोसायटी से आप क्या चाहते हैं?

**श्री उपसभापति:** प्लीज, आप कनक्लूड कीजिए।

**डा॰ मुरली मनोहर जोशी:** सर, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। आप क्या करना चाहते हैं? किस तरफ आप आतंकवाद की लड़ाई को ले जाना चाहते हैं? अगर आपको आतंकवाद की लड़ाई लड़नी है तो एक फर्म पॉलिसी बनाइए, सब पार्टियों की राय से बनाइए, एक्सपर्ट्स की राय से बनाइए, इंटरनेशनल सिचुएशन और इंटरनेशनल टेकनोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाइए और उस पर दृढ़ता के साथ काम करिए। मैं देश की सभी पार्टियों से यह अनुरोध करता हूं कि यह कोई

*[]Transliteration in Urdu Script.

पार्टी पॉलिसी का सवाल या वोट बैंक का सवाल नहीं है, यह देश की सुरक्षा का सवाल है। सारा विकास ध्वस्त हो जाएगा-अगर एक एयरपोर्ट नष्ट हो जाए तो हजारों करोड़ रुपए नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आतंकवाद की जितनी भी डायमेंशंस हैं, उन पर आप खुलकर बात करिए और एक राय बनाइए। भगवान के वास्ते देश की सुरक्षा के लिए पार्टियों और सरकारों का ध्यान मत कीजिए। अगर आप कोई ऐसे कारगर कदम उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपकी इसमें पूरी सहायता करेगी, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद से मुकाबला करने में डटकर आपके साथ आएगी, बशर्ते कि आप एक सर्वसम्मत नीति इस बारे में बनाएं। उपसभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मसले पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, this is a clarification on Statement. Let us not convert it into a full-fledged discussion. *(Interruptions)* Keeping the importance of the issue ...*(Interruptions)*... Yes, you can make mention of ...*(Interruptions)* But please keep in mind that you have to seek specific clarifications. Instead of seeking all the general ...*(Interruptions)*

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): In the morning, it was decided that it would be a discussion. *(Interruptions)* I am making this submission with due respect. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ahluwaliaji, I am seeking your cooperation for running the House smoothly. But, at the same time, let us not convert it into a full-fledged discussion. Let there be no repetitions. *(Interruptions)*

**श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** रेपिटिशन नहीं है, किन्तु यह ईशू बहुत सेंसेटिव है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, we can have a full discussion on internal security. *(Interruptions)*

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): What is this, Sir? *(Interruptions)* Let us continue the discussion. *(Interruptions)*

**श्री शाहिद सिद्दिकी:** सर, इस पर हमारा नोटिस था। आपने कहा था कि इस पर डिसकशन होगा ...(**व्यवधान**).... आपने आश्वासन दिया था। ...(**व्यवधान**)...

†[] **شری شاہد صدیقی :** سر، اس پر ہمارا نوٹس تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ اس پر ڈسکشن ہوگا ۔مداخلت۔ آپ نے آشواسن دیا تھا ۔مداخلت۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You see, I have to convey that this is a statement. *(Interruptions)* I have to say that these are the rules for a statement. *(Interruptions)*

**श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** वह तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You yourself say ...*(Interruptions)*... हम क्या कर सकते हैं? श्री राजीव शुक्ल।

**श्री राजीव शुक्ल** (महाराष्ट्र): धन्यवाद महोदय, सबसे पहले इन घटनाओं की मैं कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं और जो जान-माल का नुकसान हुआ, उसके लिए दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सर, आपने कहा कि इस पर केवल क्लैरीफिकेशंस करिए, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से इस मामले में कुछ बातें जानना चाहता हूं। सबसे बड़ी चीज यह है कि इन घटनाओं में अब तक क्या पता चला है कि क्या स्थिति है और कौन सा ग्रुप इसके लिए जिम्मेदार था? क्या उसके सीमा पार कोई ताल्लुक थे या नहीं थे? एक संगठन ने ई-मेल के जरिए क्लेम भी किया है। तो वह कौन सा संगठन है, क्या उस मामले में सरकार को कोई जानकारी प्राप्त हुई है? दूसरी बात यह है कि जैसा जोशी जी ने आरोप लगाया कि गंभीरता नहीं दिखाई गई तो मंत्री जी के बयान में कई जगह इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से केन्द्र और राज्य सरकार ने मिलकर तमाम कदम उठाए हैं और एन॰एस॰जी॰ की टीम ने जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां पर जाकर पोस्ट इंवेस्टिगेशन का काम शुरू किया है। इसके अलावा यू॰पी॰ गवर्नमेंट की एस॰टी॰एफ॰ के साथ मिलकर तफ्तीश भी चल रही है। तो उसमें क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि इस सिलसिले में तकरीबन नौ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो उस मामले में भी सरकार अगर कुछ अवगत करा

†[]Transliteration in Urdu Script.

सके तो अच्छा होगा। इसके अलावा सारी जगह जहां अदालतें हैं सब जगह पर सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया गया, खास तौर से इलाहाबाद और लखनऊ हाई कौर्ट में। इसका भी जिक्र मंत्री जी ने किया है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो एक जनरल एडवाइजरी केन्द्र सरकार से जाती थी हर राज्य सरकार को कि भीड़ भरे जो इलाके हैं या सार्वजनिक स्थान हैं वहां पर एहतियात के तौर पर सुरक्षा प्रदान की जाए। तो वह रेग्यूलर अभी जा रही थी या नहीं जा रही थी और कोई एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी या नहीं दी गई थी? तीसरी चीज यह है कि इस घटना से कुछ दिन पहले लखनऊ में तीन टेरोरिस्ट पकड़े गए थे और उन टेरोरिस्ट ने यह कहा था कि हम कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। तो उनका बयान अपने आप में एक ऐसा तथ्य था कि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की कोई सूचना की जरूरत रह जाती, जोशी जी फिर भी इस बात पर लगातार इंसिस्ट कर रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से वह भी जानना चाहता हूं कि उसके बाद की क्या स्थिति होती अगर इस तरह का कोई बयान किसी टेरोरिस्ट का आता है। सर, इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि यह समस्या कोई एक राज्य के किसी एक राजनीतिक दल की समस्या नहीं रह गई है, यह पूरे देश की समस्या है, एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। मैं नहीं समझता कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार यह दावा कर सकती है कि उसके शासन में आतंकवादी गतिविधियां नहीं हुईं। अब इस देश में कोई पौलिटिकल पार्टी और कोई गवर्नमेंट बाकी नहीं बची है जिसके जमाने में आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई हों। इसलिए इसको सबको मिलजुल कर लड़ने की बात तो समझ में आती है कि सब लोग मिलकर इस लड़ाई में शामिल हों, बजाए इसके एक दूसरे पर दोषारोपण करके इससे अगर हमें कोई फायदा मिलता हो तो मुझे नहीं लगता कि उसका कहीं कोई नतीजा निकलने वाला है। आज जोशी जी इस बात पर जोर दे रहे थे कि सरकार गंभीर नहीं है। मैं इनसे पूछ सकता हूं कि जब संसद पर हमला हुआ था तो क्या सरकार गंभीर नहीं थी? जब अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ क्या तब सरकार गंभीर नहीं थी? क्या ....**(व्यवधान)**

**श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** यह सब कह कर तो ....**(व्यवधान)**

**श्री राजीव शुक्ल:** जरा सुनो। मैं तो खुद कह रहा हूं कि क्या सरकार गंभीर नहीं थी, यह सवाल पूछ रहा हूं। .... **(व्यवधान)** जब लाल किले पर हमला हुआ था तब क्या सरकार गंभीर नहीं थी? ....**(व्यवधान)** उनका कहना है कि सरकार गंभीर नहीं थी। ....**(व्यवधान)**

**श्री विनय कटियार** (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, फिर हमें भिंडरावाले से शुरू करना पड़ेगा। ....**(व्यवधान)**

**श्री उपसभापति:** आप बैठिए। ....**(व्यवधान)** कटियार साहब, आप जो चाहते हैं वे नहीं बोलेंगे और वे जो चाहते हैं आप नहीं बोलेंगे। बोलने दीजिए न उनको। ....**(व्यवधान)**

**श्री विनय कटियार:** हम आपका संरक्षण चाहते हैं। हम तो व्यापक चर्चा चाहते हैं ऐसा ही नोटिस दिया है। ....**(व्यवधान)**

**श्री राजीव शुक्ल:** विनय जी, अगर इस घटना के बारे में पूछो तो जैश-ए-मोहम्मद का नाम आ रहा है। अगर जैश-ए-मोहम्मद की पुराण हमने निकालनी शुरू की तो आपने ही अफगानिस्तान जाकर उसके मुखिया को छोड़ा था। तो यह वहां से शुरुआत हुई है, मौलाना अजर महमूद से शुरूआत हुई है। ....**(व्यवधान)** फिर मैं भी अजर महमूद पर जाऊंगा। ....**(व्यवधान)**

**श्री विनय कटियार:** उस मीटिंग में आप थे और क्या आपने विरोध किया था। ....**(व्यवधान)**

**श्री राजीव शुक्ल:** मैं उस मीटिंग में नहीं था।

**श्री विनय कटियार:** उस समय आप को-आर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे। उसमें आप थे, क्या आपने विरोध किया था? ....**(व्यवधान)**

**श्री राजीव शुक्ल:** मैं उस कमेटी में नहीं था, मैं आपकी केबिनेट में नहीं था। ....**(व्यवधान)**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*.. He has not yielded. ...*(Interruptions)*... देखिए, आप बैठिए।

**श्री राजीव शुक्ल:** इतनी घटनाएं हुई हैं पूरे राष्ट्र में हर सरकार के जमाने में। अहलुवालिया जी से पूछ लो न बगल में बैठे हैं, वे आपको कश्मीर पर सब बता देंगे। इसलिए मान्यवर, वहां जितनी भी घटनाएं हुई हैं चाहे उत्तर प्रदेश की हों, चाहे किसी राज्य सरकार की हों, या कोयम्बटूर की हों, पूरे देश में एक आतंकवाद का माहौल चल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में आईएसआई का नेटवर्क बन गया है, आतंकवादियों का नेटवर्क बन गया है, तो यह कोई एक दिन में नहीं बन गया है, वह आतंकवाद का नेटवर्क कम से कम पांच-छह साल में बना होगा। ...(**व्यवधान**)... जिसने उस नेटवर्क को बनाने में मदद की वह पाकिस्तान भी आज इसका शिकार हो रहा है। आज सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान है। यह एक ऐसी समस्या है कि ...(**व्यवधान**)... इस समस्या से हम सब को मिलकर लड़ना पड़ेगा और मैं सरकार से, गृह मंत्रालय से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके बारे में क्या कार्यवाही हुई है? क्या इसके लिए एहतियाती कदम उठाये गये हैं? इसके अलावा आगे इस आतंकवाद के नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाये, तराई के इलाकों में जो आतंकवाद का नेटवर्क बनता जा रहा है, उसको कैसे रोका जाये, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद।

**श्री अमर सिंह:** धन्यवाद, उपसभापति जी। सबसे पहले तो यह जो दुखदायी घटना हुई है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और मारे गये लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं। हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने विशेषकर डा॰ मुरली मनोहर जोशी जी ने, भाई राजीव शुक्ल जी ने अपने वक्तव्य में आतंकवाद से मिलजुल कर लड़ने की बात कही है, इससे मैं सहमत हूं। मैं मानता हूं कि इस तरह के क्रियाकलापों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर के हमें इस पर विचार-विमर्श करना चाहिए। खेद का विषय है कि कोई भी जगह आज हिन्दुस्तान में सुरक्षित नहीं है। जिस संसद में बैठकर आज हम यह बहस कर रहे हैं, इस पर हम आक्रमण झेल चुके हैं, हम लाल किला पर हमला देख चुके हैं, चाहे रघुनाथ मंदिर हो, चाहे अक्षरधाम मंदिर हो, हमने इन पर आतंकवादी हमला देखा है। प्रश्न यह नहीं है कि किस शासन काल में ऐसा हुआ है, लगातार अनवरत रूप से यह हमला होता जा रहा है। अब न्यायपालिका बची थी, न्यायपालिका के ऊपर, वकीलों के ऊपर ठीक उस समय, जिस समय काफी भीड़ होती है और ठीक एक समय में सवा बजे बम विस्फोट किये गये। कल मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी, चन्द्रबाबू नायडु जी, चौटाला जी के साथ फैजाबाद, बनारस और लखनऊ तीनों जगह पर गया था। हमने देखा कि वहां पर बहुत हृदय विदारक दृश्य था। वहां पर भीड़ में, जहां काफी लोग थे, एक ही पद्धति से साइकिल से, अमोनियम नाइट्रेट के माध्यम से, डिटोनेटर लगाकर एक ही समय में लगभग तीनों जगहों पर विस्फोट किये गये। फैजाबाद और अयोध्या में कोई अंतर नहीं है और अयोध्या, बनारस और लखनऊ तीनों जगह पर साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ये हमले किये गये। मैं एक बुनियादी बात कहना चाहता हूं, बहुत विनम्रता के साथ शासक दल से कहना चाहता हूं कि हमारे भी राजनैतिक विरोध रहे हैं। इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि जब संकटमोचक मंदिर पर हमला हुआ था और उसके पहले भी जब अयोध्या में मुलायम सिंह जी के शासनकाल के दौरान आक्रमण हुआ था, यहां पर जायसवाल जी उपस्थित हैं, वह हमारे उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, वह गृह राज्य मंत्री हैं, तमाम राजनैतिक विरोध के बावजूद केन्द्र सरकार से हमारा पूरा समन्वय था और पूरी सहयोगिता थी। उस मामले में यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी बयान आया था कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शिवराज पाटिल जी, मुलायम सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री जायसवाल जी सब लोगों ने मिलजुलकर काम किया था, इसलिए आज यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक हफ्ते पहले तीन आतंकवादी पकड़े जाते हैं और प्रदेश के हर बड़े-बड़े दल के नेताओं की सूची देते हैं, वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उन लोगों को निशाने पर बनाये थे, इसके बावजूद मुख्य मंत्री का बयान आता है कि केन्द्र ने हमें सूचना नहीं दी। लखनऊ में डीआईजी बैठते हैं, हर मुख्य मंत्री का यह दायित्व होता है कि वह डीआईजी से मिले, बातचीत करे। जब एक हफ्ते पहले कुख्यात आतंकवादी पकड़े गये हैं और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि बड़े-बड़े नेता उनके निशाने पर हैं, तो आपको कौन-सी अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा श्रीप्रकाश जायसवाल जी से, शिवराज पाटिल जी से या केन्द्रीय सरकार से थी? जब आतंकवादी पकड़े गये और पकड़े गये आतंकवादी यह स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े-बड़े नेता हमारे निशाने पर हैं, इसके बावजूद आप मौन हैं और केन्द्र सरकार के सिर पर ठीकरा तोड़कर अपने दायित्व से, पूर्ण बहुमत में चल रही सरकार मुक्त होना चाहती है, यह बड़ी निराशा का विषय है। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक पुरानी बात हमें याद आती है, When Rome was burning, Nero was laughing. जब रोम जल रहा था, तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। वहां पर फैजाबाद में, बनारस में और लखनऊ में बम विस्फोट हो रहे हैं और मुख्य मंत्री मुम्बई में ...(**व्यवधान**)...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA ( Uttar Pradesh): Sir, this is not permissible. ...*(Interruptions)*... Sir, I rise to say that somebody who is not in the House ...*(Interruptions)*... the hon. Member is trying to raise... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He can answer. It is not an individual... ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir, I request ...*(Interruptions)*... that he should confine to this; he should not bring party politics over here. It is a pittance, ये बहुत छोटी हरकत कर रहे हैं। हमें माननीय अमर सिंह जी से ऐसी उम्मीद नहीं है। ये इस हाउस के इतने सीनियर मैम्बर हैं, अगर ये यहां पर राजनीति करने आए हैं, तो इनको यह राजनीति बाहर करनी चाहिए। इनको ऐसे गंभीर विषय पर, इस तरह की राजनीति करने का अधिकार नहीं है। ..(**व्यवधान**)..

**श्री उपसभापति:** मिश्र जी, आप बैठ जाइए। ..(**व्यवधान**).. आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ..(**व्यवधान**)..

**श्री सतीश चन्द्र मिश्र:** जो विषय है, इनको उस पर ही बोलने का अधिकार है। ..(**व्यवधान**).. किसी और चीज पर ये इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। ..(**व्यवधान**)..

**श्री अमर सिंह:** सारा अधिकार आप लोगों को है? ..(**व्यवधान**)..

**श्री उपसभापति:** आप बैठिए, आप बैठिए। ..(**व्यवधान**)..

**श्री सतीश चन्द्र मिश्र:** अगर इनकी गद्दी खिसक गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरीके से अपना दर्द निकालेंगे। ये राष्ट्र के साथ खेल खेलने की इजाजत नहीं पा सकते हैं। ..(**व्यवधान**)..

**श्री अमर सिंह:** आपको गद्दी मिल गई है, तो आप अट्टहास करेंगे? ..(**व्यवधान**).. मैं कह रहा था। ..(**व्यवधान**).

**श्री उपसभापति:** आप किसी का नाम मत लीजिए।

**श्री अमर सिंह:** उपसभापति महोदय, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ..(**व्यवधान**)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They can mention the 'office', but not the name. ...*(Interruptions)*...

**श्री अमर सिंह:** सर, मैंने नाम नहीं लिया है और मैं आगे कोई नाम नहीं लूंगा। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि जो उनको पीड़ा हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहते हुए, अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। ..(**व्यवधान**)..

**श्री सतीश चन्द्र मिश्र:** पीड़ा तो पूरे देश को है। ...(**व्यवधान**)..

**श्री अमर सिंह:** मैं कहना चाहता हूं कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून व्यवस्था का केन्द्र सरकार के ऊपर पूरा ठीकरा तोड़ दिया है। मैं किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, 25 हजार सिपाहियों को निकाल दिया गया और 27 IPS आफिसर्स को नौकरी से हटा दिया गया। पूरी की पूरी फोर्स .. (**व्यवधान**)..

**श्री सतीश चन्द्र मिश्र:** मान्यवर, ये उत्तर प्रदेश सरकार में, असेम्बली में क्वेश्चन रेज़ कर चुके हैं और वहीं पर दोबारा भी कर सकते हैं, ...(**व्यवधान**)..

**श्री उपसभापति:** अमर सिंह जी, अमर सिंह जी ..(**व्यवधान**)..

**श्री अमर सिंह:** यह गलत बात कही है ...(**व्यवधान**).. 27 IPS आफिसर्स ...(**व्यवधान**)..

**श्री सतीश चन्द्र मिश्र:** लेकिन पार्लियामेंट में इस तरह के सवाल ...(**व्यवधान**).. इश्यु रेज़ करेंगे ...(**व्यवधान**). यहां पर ये यूपी स्टेट असेम्बली कन्वर्ट कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**).. यह पार्लियामेंट हैं, यूपी स्टेट असेम्बली नहीं। ... (**व्यवधान**)..

**श्री शाहिद सिद्दिकी:** आज आतंकवाद इसलिए नया है कि आपने पुलिस को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है। ...(**व्यवधान**)..

†[شری شاہد صدیقی : آج آتنک واد اس لئے نیا ہے کہ آپ نے پولس کو پوری طرح سے تہس نہس کر دیا ہے ۔مداخلت۔]

**श्री सतीश चन्द्र मिश्र:** इनको यह मालूम होना चाहिए, ...(**व्यवधान**).. यह यूपी स्टेट असेम्बली नहीं, जो वहां के सवाल यहां उठा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)..

**श्री उपसभापति: यह क्या हो रहा है?** ...(**व्यवधान**).. are we serious in discussing the issue of bomb blasts or are we just ... *...(Interruptions)...*

**श्री अमर सिंह:** यह पुलिस सिस्टम को ...(**व्यवधान**)..

**श्री सतीश चन्द्र मिश्र:** अभी कल जाकर इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमारे 25 हजार वर्कर्स निकाल दिए गए हैं। ...(**व्यवधान**).. अगर इनके वर्कर्स निकाल दिए गए हैं तो इसमें इनको दर्द, पीड़ा है तो इसके बारे में इनको बोलना चाहिए। ...(**व्यवधान**)..

**श्री उपसभापति:** देखिए, प्लीज, आप बैठिए, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**).. Please confine the discussion only to the bomb blasts. Let us not extend it. *...(Interruptions)...* देखिए, यूपी हो या कोई भी हो . ..(**व्यवधान**).. My request is, please confine to the issue because the discussion is for limited purpose; we are not discussing the entire thing. *...(Interruptions)...* Please confine to the issue. *...(Interruptions)...*

**श्री अमर सिंह:** सर, मुझे मिश्र जी बोलने दें। ...(**व्यवधान**)..

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, are you going to keep words like* in your records? *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Pardon please.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, he is saying, * Are you going to keep that in the record? *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; that has not gone on record. *...(Interruptions)...* That has not gone on record. *...(Interruptions)...* You see, anybody who is speaking without permission will not go on record. *...(Interruptions)...*

DR. FAROOQ ABDULLAH (Jammu and Kashmir): But how do you stop that from going on the television? *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That we can discuss. *...(Interruptions)...*

**श्री अमर सिंह:** सर, IPS उत्तर प्रदेश का नहीं होता है। उसको हटाने के लिए गृह मंत्री हैं और केन्द्र से अनुमति लेनी पड़ती है और IPS केन्द्र के द्वारा गवनर्ड होता है। सर, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि घटना उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश का जिक्र तो होगा ही। गृह राज्य मंत्री जी, कल लखनऊ में वकीलों ने बताया था और वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज भी थे, घटना के बाद 6 घंटे तक एक बम पड़ा रहा और 6 घंटे बाद पता चला कि एक बम पड़ा है, जो कि फटने वाला है। लखनऊ के अदालत परिसर में 6 घंटे तक वह बम पड़ा रहा और उस बम को पुलिस ने छुआ तक नहीं। महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो कुख्यात आतंकवादी पकड़े गए थे, उन्होंने माना कि कई बड़े नेता उनके निशाने पर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं विधान सभा में प्रश्न पूछा गया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सरकार की तरफ से मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा कि 25 संवेदनशील जिले हैं, जहां पर आतंकवादियों की गतिविधियां हो रही हैं। ...(**व्यवधान**)..

**श्री उपसभापति:** वह मत लाइए।

**श्री अमर सिंह:** मैं कह रहा हूं कि आपको किस बात की सूचना चाहिए थी। जब आपने विधान सभा में माना है कि 25 जिले अति संवेदनशील हैं और वहां आतंकवादी हैं तो आप केन्द्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी सौंप कर, बच नहीं

---

***Expunged as ordered by the Chair.**

**†[ ]Transliteration in Urdu Script.**

सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार ने कोई सहयोग मांगा है तो इसका विवरण दें। आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने सहयोग नहीं दिया है अगर सहयोग मांगा है और आपने नहीं दिया है, तो यह आरोप सत्य है, लेकिन अगर कोई सहयोग मांगा ही नहीं गया और चार आतंकवादी पकड़े गए, उन आतंकवादियों का कन्फैशन है।

विधान सभा में सरकार की ओर से बयान आया है कि 25 जिले संवेदनशील हैं, इसके बावजूद भी छः-छः घंटे तक लखनऊ कोर्ट के परिसर में बम पड़ा रहता है, उसको छुआ नहीं जाता है, यह बहुत ही गंभीर बात है। वहां पर जो सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर आई है, उस सरकार में कभी श्रावस्ती कांड होता है, कभी फैजाबाद में बलात्कार होता है।

जैसा कि अभी जोशी जी ने कहा कि विधायकों की सुरक्षा घटा दी गई है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पर मुलायम सिंह जी की सुरक्षा हटा दी गई, मेरी सुरक्षा हटा दी गई, आपकी सुरक्षा भी हटा दी गई, जोशी जी, आप और हम, सभी देश के लिए अपने काम करते हुए खेत हो जाएं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम सुरक्षा की भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सुरक्षा के बिना रहना चाहते हैं। हमें कोई सुरक्षा न दी जाए। न केन्द्र सरकार की ओर से दी जाए न राज्य सरकार की ओर से दी जाए। लेकिन यह सनद रहे कि किस तरह आतंकवाद के साये में, इनके प्रशासन में सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो कर एक-दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रही है। यह बात इस भावना के प्रतिकूल है, जिस भावना को सदन में सबने उठाया है कि आतंकवाद एक ऐसा मसला है जो हर दल से, हर पार्टी से इतर, एक व्यापक समस्या है। इसका मुकाबला हम सब लोगों को मिल-जुल कर करना चाहिए। इसका मुकाबला कोका या कोटा से नहीं होगा, इसका मुकाबला हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति से, मनोबल से, मजबूत इरादों से और संकल्प से होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, at the outset, I wish to state that my party, the Communist Party of India (Marxist), unequivocally condemns these terrorist attacks that have taken place. We deeply mourn the loss of lives and the injuries that have been sustained. But, at the same time, it is not merely a question of expressing concern and condemnation because the choice of places that have been chosen by the terrorists is also very ominous. The fact that the judicial arena, which was outside the purview of terrorist attacks so far, has also been drawn into their orbit and that in courts such explosives were planted and they could actually cause such a large number of deaths is ominous and this is a warning that the Government must take very seriously.

Sir, I do not know whether you are permitting a discussion or allowing us only to seek clarifications but since it is taking the form of a discussion, I would like the Minister also to apprise us of the level of Intelligence that is there is our country today and whether there are any serious lapses that are occurring and why these are not being corrected. We cannot see these blasts only in isolation; in the last so many months we had a series of blasts taking place all over the country, at the Mecca Masjid in Hyderabad, in the city of Hyderabad, and now, in Varanasi, Faizabad and Allahabad. In all these places, why is it that the Intelligence apparatus is not able to forewarn us? Now, this is a serious issue which needs to be gone into in depth and I hope the Government will be able to do so and apprise us in the Parliament as to why the process of being forewarned in such attacks is not taking place.

Sir, I refer to para 8 of the Minister's statement. We fully appreciate the concern of the Government and the fact that the flight against terrorism has to be fought at different levels and involving the civil society and the media is also very important; we fully understand this. But the question that we have to understand now, and which is very important in my opinion, is that it will be very unfortunate if we were to bracket all these terrorist attacks into some sort of a straitjacketed Muslim extremism or Muslim terrorism. We have been victims of terrorist attacks that run across all forms of religious affiliations and all forms of regional affiliations. In fact, we have lost two of our Prime Ministers to such attacks, and the perpetrators of these assassinations had nothing to do with Muslim terrorism or Muslim

extremism. Therefor, let us not confront this only with ideological blinkers, as some people have said, in order to target one community. If the Minister and the UPA Government are sincere about para 8 of theirs, then the atmosphere has to be created of sincere security amongst the minorities in our country. On that, we are still appalled as to why in spite of the Sachchar Committee recommendations, in spite of the status of the minorities that has come before all of us, even now action on that report is not proceeding. We would like to warn the UPA Government that no action on that count will be tantamount to succumbing to pressures of the principal Opposition's charge that they are suffering from Muslim appeasement, and they cannot afford that charge to be labelled against them. Therefor, immediate action must be taken on that score. The point is to create the confidence amongst the minorities and, I think, that in targeting the courts one of the messages that is being sent is that, yes, the guilty must be brought to book and those who are perpetrating such crimes must be brought to book. But in the name of bringing the guilty to book, innocent people should not be harassed and innocent people should not be hounded and that is the responsibility that the Government will have to take. This is very important. As we all agree, fight against terrorism is not merely a law and order question. When we had POTA adorning the statute book, you had attacks and very vicious terrorist attacks that took place even on this Parliament, on the Red Fort, on the Akshardham Temple and on the Raghunath Temple. So, it is not a question of lack of law. What is required is a concerted, united and a concentrated determination to get rid of this problem and this menace and that is what we have to work for and let us not divert the attention into saying whether laws are adequate or not. If you want the larger issue to be taken up, as has been said in para No. 8 not only the question of creating confidence amongst the minorities, but also the question of mobilising a larger opinion in marshalling all the patriotic forces that we have in the fight agaist terrorism becomes very important. Since the reference has been made. I would also like to refer to the question of Taslima Nasreen's issue. The question is whether she will be here or not or whether her visa will be extended or not which is the exclusive prerogative of the Central Government and they will take decision on that issue. But once she is allowed to live in our country -- and where she will live in our country, the Central Government can decide -- the protection has to be given. But this has to be a universal principle for everybody. You cannot stop Maqbool Fida Husain from entering India because he has allegedly hurt some sections religious sentiments and now plead for security to Taslima. This duplicity cannot be allowed. And one of the most illustrious sons of our country, Fida Husain, is charged by saying 'you hurt our religious sentiments.' But what Taslima will do? For her, you want protection, but for Husain you adopt a different standard, this cannot be allowed. ...*(Interruptions)*... Fight against terrorism ...*(Interruptions)*... Sir, I am not yielding ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: he is not yielding. Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI VINAY KATIYAR: *

SHRI SITARAM YECHURY: Through you, Sir I would like to tell Mr. Narayanasamy that the point I am raising is that in the fight against terrorism, you cannot be discriminatory. You cannot say that different standards will apply to Husain and different standards will apply to Taslima ...*(Interruptions)*... Sir, three years' protection has been given in Bengal and it will again be given if you extend the visa. ...*(Interruptions)*...'You' means the Government and that is your decision. What do you want to do?

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN) in the Chair.]

*Not recorded.

So, let us not divert ourselves into these issues. If sincerely you want to fight against terrorism, let us not bring in your partisan politics here in the fight against terrorism in which case you are only encouraging the terrorists and you are not fighting terrorism. So, therefore, in a united fashion, if we all believe that, yes, terrorism is a menace that has to be fought, then whether it is LTTE, whether it is North-Eastern terrorist, or whether it is muslim organisation, all of them must be treated on par, and there cannot be any discrimination between the two to suit your or somebody else's political purposes and objectives. Therefor, Sir, on this particular issue, I don't think that we should get diverted onto the question of imposing new draconian laws like POTA or bringing in other issues to suit our political purposes. Let us, as Indians, today, stand firm and united, saying any expression of terrorism which comes from any corner that will have to be fought and let us not be victims of a clash of civilisation argument that is taking place. And that is the language of US imperialism and that is the language which we are also seeing here with the principal Opposition party which is not acceptable to us an Indians and, therefor, what I am again re-emphasising is that the fight against terrorism will have to be unitedly taken up and done without putting on ideological blinkers. We have lost many stalwarts in our country as a result of this terrorist activity from the *Mahatma* down to two Prime Ministers and to many other thousands. Let us now marshal our forces, brace ourselves to actually root out this problem through a united effort. I would request the UPA Government to sincerely implement para 8 of the Minister's statement drawing all the sections that can be drawn in this fight against terrorism and create that confidence among the minorities and among every else who are aggrieved that solution to their grievances cannot be by terrorist methods. That sort of a confidence has to be created, and I hope that the Government will take these measures and steps in this direction.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): On behalf of the AIADMK Party, I strongly condemn the serial bomb blasts in U.P. on 23rd November. Three months ago, on 29th August, we debated about the Hyderabad bomb blast. I do not know when we will be debating again about yet another bomb blast in the next few weeks or months. In the last debate on the Hyderabad bomb blast, I had demanded from the Home Minister a White Paper on the various terrorist attacks that took place in the country during the last three-and-a-half years of the UPA rule. But, nothing has been done. Now, the Government has come out with a routine and a bland statement. I charge that the UPA Government is taking the issue of terrorism very lightly and casually. The blasts in U.P., Hyderabad, Malegaon, etc., are only outward symptoms; the root cause of the disease is that the UPA Government has no plan or proposal or vision for tackling terrorism. It is routinely said that the I.B. has alerted the State Governments; whether it is Hyderabad bomb blast, or an alert to Chennai, or now, the I.B. has given alert to U.P. It looks as though the Central Government is acting only like a messenger or a postman. Is it enough if the message is simply passed on to the State? What is the role of the Central Government in all these cases? The biggest blunder committed by the UPA Government is the repeal of POTA for political considerations. This, coupled with the soft approach of the UPA Government towards tackling terrorism, has emboldened the terrorists to strike with that will. What is needed is the political will and the firm resolve to fight terrorism with an iron hand. I urge the Central Government to immediately bring back the POTA and tell the citizens of this country that it is serious about the security of the country.

**श्री मंगनी लाल मंडल** (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज सदन में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और सरकार से क्लैरीफिकेशन चाहते हैं, यह विषय किसी राजनीतिक दल, किसी सरकार का विषय या किसी प्रदेश से संबंधित भी नहीं रह गया है। लेकिन मैं अपनी बात कहूं या माननीय मंत्री जी से क्लैरीफिकेशन पूछूं, क्योंकि आसन के माध्यम से सदन ने इस की निंदा की है और अपनी संवेदना मृतक व्यक्तियों के प्रति व्यक्त की है, मैं भी सबसे पहले अपनी ओर से अपनी पार्टी की ओर से मृतक व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

महोदय, ऐसी बात प्रारंभ होती है और डा॰ मुरली मनोहर जोशी सहित कई माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि सरकार इस विषय के प्रति गंभीर नहीं है, मैं और मेरा दल इस बात से सहमत नहीं है। अभी स्वयं माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उस के खंड 7 और 8 में सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपनी वचनबद्धता, अपनी प्रतिबद्धता का इजहार किया है और उसे सदन के सामने भी रखा है। महोदय, दो-तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से जूझ रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान का मामला और हमारा मामला एक है। अभी अमरीका के वैदेशिक मामलों का एक प्रतिवेदन आया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले बीस वर्षों में पाकिस्तान को विकास के मद में जितनी आर्थिक सहायता दी गई है, उन तमाम पैसों का दुरुपयोग उसने भारत के खिलाफ आतंकवाद को आश्रय देकर किया है। ...(**व्यवधान**)... और यह सामान खरीदता था, आदरणीय फारूक साहब कर रहे हैं। पाकिस्तान तो आतंकवाद का जन्मदाता है, हम तो आतंकवाद से बीस वर्षों से लड़ रहे हैं और पाकिस्तान ने जिन आतंकवादी संगठनों को जन्म दिया, आज उनके पालन-पोषण में थोड़ी कमी कर दी गई है, तो आज वहीं आतंकवादी उनसे लड़ रहे हैं। आज आतंकवादी बर्फ पिघलने से पहले हमारे देश में प्रवेश करने की घात में भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी समस्या और उनकी समस्या एक नहीं है। वह लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मगर हम बीस सालों से आतंकवादियों से जूझ रहे हैं। इसलिए हमारी यह समस्या न किसी प्रदेश की है, न किसी पार्टी की है, बल्कि एक राष्ट्रीय समस्य है, जिसका बीस वर्षों से हम बहुत ज्यादा दंश झेल रहे हैं। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, इस पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह कानून और व्यवस्था का विषय न होकर आज एक लोक-व्यवस्था का विषय बन गया है। चाहे बाजार हो, हाट हो, मंडी हो, शिक्षण संस्थान हो, न्यायालय हो, हर जगह लोग आज सहमें हुए हैं, दहशत में हैं। ये आतंकवादी पहले जिन ठिकानों पर आक्रमण करते थे, आज उनका स्थान बदल गया है और जो इन आतंकवादियों का घिनौना चेहरा है, उस चेहरे का स्वरूप भी बदल रहा है। इसलिए सरकार को अपनी रणनीति में परिवर्तन करना होगा। अभी उत्तर प्रदेश में जो तीन जगहों पर घटनाएं घटीं, उस पर अगर राज्य सरकार ने कहा है कि हमें समय पर जासूसी, खुफिया सूचना नहीं मिली, तो सरकार को सदन में यह बताना होगा कि राज्य सरकार ने जिन तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें सरकार को सफलता मिली थी, उन तीन आतंकवादियों ने गिरफ्तार होने के पश्चात् बंद कमरे में जो खुलासा किया, बयान दिया, उसके बाद जो तथ्य उद्घाटित हुए, उस आलोक में केन्द्र और राज्य का विचारों के और सूचनाओं के आदान-प्रदान करने के मामले में समन्वय रहा या नहीं रहा? इस बिन्दु पर मैं जानना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी इसको क्लेरिफाई करें, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। पहला प्रश्न।

दूसरा, यह मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं घटी हैं। पहले धार्मिक स्थानों पर घटनाएं घटती थीं, दूसरी जगहों पर घटती थीं, अब न्याय मंदिरों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। कई माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है कि इस बारे में केन्द्र और राज्य का समरूपता के आधार पर कौशल बनाना चाहिए। इस देश में जो राज्य सरकारें हैं, उनका जो प्रशासनिक तंत्र है, जो पुलिस तंत्र है जो खुफिया तंत्र है और जो केन्द्र का खुफिया तंत्र है, इनके बीच में क्या कोई समरूपता के आधार पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कोई रणकौशल बना है या नहीं बना है? और, उसका आधुनिकीकरण हुआ है या नहीं हुआ है ? दूसरा क्लैरिफिकेशन हम यह जानना चाहेंगे।

सर, मंत्री जी सदन से चले गए। तीसरी बात, अभी तक जो हमको जानकारी मिली है, उसके अनुसार इस देश में कई आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। अभी एक तो इंडियन टेररिस्ट का नाम आदरणीय डा॰ जोशी जी ने लिया है, विदेशों में भी यह आतंकवादी संगठन इस देश को बदनाम करने के लिए काम कर रहा है, इसके अलावा इस देश में अभी तक कई आतंकवादी संगठन हैं, लश्कर-ए-तैबा है, जो जग-जाहिर आतंकवादी संगठन है, जिससे हम सब परिचित हैं, फिर हिजबुल-मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, अलजहाद फोर्स, अलमुजाहिद फोर्स, हरकत-उल-अंसार, इसबान-उल-मुजाहिदनी, असवर्क कश्मीर जेहाद फोर्स, मुताहिदा युनाइटेड कौंसिल, स्टुडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी और एक नया संगठन आया है, जो अभी वाराणसी में और दूसरी जगहों में घटनाएं घटी हैं, गुरु

असहदीन इसके अलावा कहा गया है कि हूजी जो संगठन है, वह इंडियन टेररिस्ट के नाम से अपनी नाम परिवर्तन कर लिया है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि ये जो आतंकवादी संगठन इस देश में सक्रिय हैं, इनके अलावा और कितने ऐसे संगठन सक्रिय हैं? सरकार को इस सदन में यह बताना चाहिए, क्योंकि यहीं संरक्षण मिलता है, यहीं वह लोगों को नेटवर्क में शामिल करता है, यहीं वह साइबर कैफे चलाता है, अब होटल चलाने लगा है, फुटपाथ पर होटल खोलने लगा है, ऐसे-ऐसे आतंकवादी संगठन हैं, जिसमें जो बाहर के लोग आ रहे हैं और यहां उनको वह शामिल कर रहा है, जो छोटे-छोटे व्यवसाय करके महीनों तक संरक्षित हैं और फिर देश के दूसरे भाग ही नहीं, दिल्ली आतंकवादियों का आश्रयस्थल बना हुआ है। दिल्ली पुलिस अगर बहुत सक्षम है, दिल्ली की सरकार अगर बहुत सक्षम है, तो दिल्ली में आतंकवादियों को आश्रय भी, shelter भी मिला हुआ है, दिल्ली सबसे बड़ा केन्द्र भी है। इसलिए सरकार को, यह अपने ठिकाने बदल रहा है, मंदिर से लेकर न्यायालय तक, इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार ने इसमें कहा है कि मीडिया, सभी समाज, राजनीतिक दल और जनता, सबको मिलकर लड़ने के लिए कहा है। डा॰ जोशी ने ठीक ही कहा है कि जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनको हम सजा नहीं दिला पाते हैं, क्योंकि हम साक्ष्य नहीं जुटा पाते हैं और यदि साक्ष्य अदालत में आ जाता है तो न्यायाधीश आतंकी हमले से डर जाए और उनको सजा न हो सके, इसके पीछे यह शायद यह धारणा है। इसलिए इस बिन्दु को सरकार को क्लेरिफाई करना चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री शरद यादव** (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जो तीन जगह बम-विस्फोट हुए और जो जान-माल का नुकसान हुआ है, मैं उसकी घोर निन्दा करता हूं। मैं आपसे संक्षेप में यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इस बाजू के लोग हों या उस बाजू के लोग हों, देश में यह समस्या हमारा बहुत गहराई से पीछा कर रही है। जो बहस यहां चल रही है, वह निश्चित तौर पर अपने-अपने दायरे में चल रही है। हम एक दूसरे पर दोषारोपण के साथ ही इसमें राजनीतिक रंग भी दे देते हैं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री मंगनी लाल मंडल:** महोदय, मेरे नाम का करेक्शन कर लीजिएगा। मेरा नाम मंगनी लाल मंडल है, आपने बोल दिया था मंजय लाल मंडल।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I correct it. It is Mangani Lal Mandal.

**श्री मंगनी लाल मंडल:** आसन से गलती नहीं होनी चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Sorry for that mistake.

**श्री मंगली लाल मंडल:** ठीक है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Your name can never be wrongly said or written.

**श्री मंगली लाल मंडल:** एब बार और गलती हुई थी, जया जी ने ध्यान आकृष्ट किया था।

**श्री शरद यादव** (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक विकट समस्या है और इस समस्या से निबटने के लिए सरकारों को भी, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, मिलकर काम करना चाहिए और आजकल तो सरकारें बिखरी हुई हैं - कहीं हमारी है, कहीं इनकी है, कहीं उनकी है और सबकी काबलियत तोल ली गई है। पूरे देशभर में जो वातावरण है, पार्टियां ठीक से चल नहीं रही हैं, वे masse के पास जाकर जो गंभीर संकट है, उसके बारे में नहीं समझा रही हैं। अभी आपने देखा कि जब उत्तर प्रदेश के मामले में सरकार की तरफ से बयान आ रहा था, यह घटना हुए दो-तीन दिन हो गए, इस पर जरूर बयान देना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इस गंभीर मसले पर दो बार, आपने दो बार इस सदन को स्थगित किया। मैं तो जा रहा था, लेकिन रुक गया। दो बार आपने सदन को स्थगित किया, कितने गंभीर हैं आप इस पर! यानी आपकी होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? फिर अभी तीन आदमी, इस घटना से थोड़े ही दिन पहले गिरफ्तार किए गए और कहा गया कि यह श्री राहुल गांधी को घेरने आए थे, उनको किडनेप करने आए थे और अब वहां की सरकार ब्लास्ट होते ही तत्काल कह देती है कि दिल्ली से सूचना नहीं आई। सूचना होती तो क्या होता? आंध्र में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी आंध्र में, अभी है, लेकिन सूचना के

बाद उन्होंने क्या कर लिया। मैं उनकी अक्षमता पर कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो टेररिस्ट होता है, वह वक्त देखता है, समय उसके पास है, वह आदमी पकड़ता है, यह 100 करोड़ का देश है, इसमें जब तक हम masse को ठीक से अलर्ट नहीं करेंगे जनता हो हम ठीक से ताकतवर नहीं बनाएंगे, जनता के बीच में जाकर को एलर्ट नहीं करेंगे कि जो आतंकवादी हैं, जैसे मान लीजिए आज वकालतखाने में हो गया, वे अपने-अपने ठिकाने अलग बदल लेते हैं। जैसे साइकिल है, तो साइकिल के कारखाने वालों को कहना चाहिए कि उनका हरेक पर नम्बर रहेगा। वह नंबर एक जगह नहीं रहेगा, वह नंबर कभी छिपाया नहीं जा सकता है। फिर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पहले देश में राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो देश उलटा चल रहा है, उलटा हुआ है, कोई बुरी बात नहीं है। अब सूबों में लोग मुख्य मंत्री बनते हैं और फिर वे भारत पर राज करने के लिए देश भर में निकलते हैं। कानूनन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ये बड़े सूबे हैं, यहां जो मुख्य मंत्री है, वह 24 घंटे भी जगेगा, तो भी काम पूरा नहीं हो सकता है, उसे इतना alert होना चाहिए, इतना चुस्त-दुरुस्त होना चाहिए और मैं इसमें किसी एक मुख्य मंत्री को नहीं कह रहा हूं, आजकल विवाद चला हुआ है कि किसी क्षेत्र में मुख्य मंत्री बन जाओ और पूरे देश भर में घूमो, वह बुरी बात नहीं है, वह ठीक बात है, लेकिन आप घूमना चाहते हैं, तो अपनी पार्टी के किसी दूसरे आदमी को मुख्य मंत्री बना दीजिए, उसको बिठा दीजिए, वह 24 घंटे देखेगा। ये सारी समस्याएं हैं। अब कानून के बारे में विवाद है, NDA सरकार ने POTA लगाया, उस POTA के चलते बहुत से अक्लियत के लोगों को सताया गया, वह कानून ही समाप्त हो गया।। अगर कानून में कोई लूपहोल है, कोई दिक्कत है, तो उसको हमें दूर करना चाहिए। यह लड़ाई आज थमने वाली नहीं है, यह 3 ब्लास्ट्स से खत्म होने वाली नहीं है, यह लड़ाई लंबी चलने वाली है।

उपसभापति जी, मैं ज्यादा बात न करके एक बात और कहना चाहता हूं। श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्त, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, वे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, उन्होंने लिखा है 20 रुपए पर 80 फीसदी लोग इस देश में जी रहे हैं, अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो भूखों पर रहे हैं और सब तरह की दिक्कत हैं, उनको आप कैसे राष्ट्र की भक्ति का और सारी भक्तियों का पाठ पढ़ाना चाहते हैं? ''भूखे भजन न होय गोपाला''-उनको भूखा रखकर आप कैसे भजन कराना चाहते हैं? आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई हुई है, अब कांग्रेस पार्टी पता नहीं उसका क्या कर रही है। यदि आप किसी मुस्लिम मुहल्ले में जाओगे, तो इतनी गरीबी है, इतना दु:ख-दर्द, इतनी लाचारी, बेबसी, गुरबत है कि वहां से निकलना भी कभी कभी कठिन होता है, इतनी बिलबिलाती हुई आबादी बसी हुई है, रहने की जगह का ठिकाना नहीं है, वहां आप हजार रुपए, दो हजार रुपए गरीब आदमी को दे दीजिए और उसे इस्तेमाल कर लीजिए। इसलिए आतंकवाद से लड़ने का एक रास्ता नहीं होगा, कई रास्ते होंगे, जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए थे, उसके बाद आपने इन 60 वर्षों में देश को जिस तरह से नरक बना दिया है, उसमें कोई हमारा और आपका हाथ नहीं है, हम भी सरकार में रहे हैं, हम जानते हैं कि जो व्यवस्था है, उसमें इतना जंजाल है, इतनी कसावट है कि कभी आप गरीब आदमी के हक में कोई काम भी करो, तो वह जमीन पर नहीं पहुंचता है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और सतीश चन्द्र जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि मिल-जुलकर इसको किया जाए। उत्तर प्रदेश, इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, अब बिहार है, महाराष्ट्र है, ये बड़े सूबे हैं और उनको जिम्मेदारी जनता ने दी है। कानून और व्यवस्था के साथ-साथ, ये जो तीन ब्लास्ट्स हुए हैं, यह कम जिम्मेदारी नहीं है, वह राष्ट्र की जिम्मेदारी है। उसमें हमें राजनीतिक तौर पर नहीं बोलना चाहिए। मैं इस पर नहीं बोलता, लेकिन मुझे तकलीफ हुई कि वहां के मुख्यमंत्री ने तत्काल बयान दे दिया कि बाहर से खबर नहीं आई थी, मैं मानता हूं कि खबर भी होगी, तो क्या करोगे, इतना बड़ा सूबा है। तो मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूं, यदि सरकार के पास खबर भी आ गई, तो क्या करोगे? इस तरह का लुंज-पुंज तंत्र है हमारे पास, चाहे वह यहां का IB हो, चाहे वह यहां की इंटेलिजेंस हो, सूबों की तो हालत और बुरी है। हम खुद आंदोलन के आदमी थे, जब हम आंदोलन के आदमी रहे हैं, तो हमें मालूम है कि सूबे की, स्टेट की जो IB होती हे, उसके आदमी को हम एक समोसा खिला दें, तो वह सारी खबर बता देता है, हम खुद ही उससे खबर ले लेते हैं, ऐसी बुरी हालत है, क्योंकि अगर किसी को डंप करना है, तो उसको CID में पहुंचा दो, यानी हमने पुलिस वालों को सज़ा की जगह रखा है, अब जो आदमी सज़ा भोगने गया है, वह आदमी क्या आपकी खिदमत करेगा, सेवा करेगा? उसकी सर्विस की अच्छी कंडीशंस बनाओ। यहां सब लोग कह रहे हैं कि IB फेल हो जाती है, इंटेलिजेंस फेल हो जाती है, इसलिए फेल हो जाती है कि आप उसकी सर्विस के बारे में ध्यान नहीं देते। उसके साथ जो पुलिस वाला हे, वह तो बहुत मौज-मस्ती में है और जो दूसरा हे, वह सोचता है कि मेरे साथ वाला आदमी तो यह कर रहा है, मेरी हालत इस तरह की क्यों है? यानी आपका खबर लेने का तंत्र लुंज-पुंज है और आज सारी पार्टियां लुंज-पुंज हो गई हैं। इन पार्टियों में कोई काम नहीं हो रहा है सिर्फ हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तीन महीने के बाद दो सूबों में चुनाव आ जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद एक पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं इस सदन में भी नहीं रह पाता हूं, तीन महीने बाद, दो महीने बाद लगातार चुनाव होता है तथा पार्टियों को फुर्सत ही नहीं मिलती है। जो थोड़ी बहुत फुर्सत है उसमें हम आपस में ही लड़ने में इतने मशगूल हैं कि इसने कितना काटा, तो इसने एक काटा तो मैं चार बार इसका काटे देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह एक गंभीर संकट है, यह संकट हमारा लंबे समय तक पीछा करेगा, हमको भी लंबे समय की योजना बनाकर के इससे निपटना चाहिए।

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir, thank you for giving me this opportunity. First of all, I condemn this incident which has taken place. On behalf of my party, I condole the family members of the victims. I would like to submit that this is a situation where, as rightly said by Shri Sharad Yadav, Sitaram Yechury and other Members, we have not to take it as party politics or use this thing for the purpose of infighting. It is a national calamity which has taken place. This incident is an attack on the nation. Therefore, we should take it in that spirit. I fully agree with the statement made by the Minister of State for Home Affairs that this is a time when all of us and the whole country should stand unitedly, and not take this opportunity for the purposes of using it as an intra-party issue creating politics and using it for that as a platform. The situation has arisen which shows that this is not the incident of first terrorist attack. It has started right from this Parliament, it has gone into the temples, it has gone into the Ajmer Sharief, it has gone into the institutions at Bangalore, it has gone into other places. For example, bomb blasts in the market places in Delhi. It is not in U.P. that the first bomb blast has taken place or some terrorist activity has taken place. It was there earlier also in U.P. in the earlier regime, there was a bomb blast inside the temple at Varanasi itself, and then at Gorakhpur. But all the parties at that time had refrained from commenting that it was on account of certain party in power not being able to control. Then our party had made a statement that this was an attack which should be condemned by all, and we should stand unitedly. Unfortunately, today the issue has been sought to be converted by some hon. Members, differently and I appeal to them that they should have a rethinking on this and see whether this should be taken as an opportunity for the purpose of intra party politics. Only a few days ago, in the State of U.P., 3 terrorists who had come with a plan which was going to affect the security of this country in a big way were nabbed by the police. Instead of appreciating and saying that they have done this. Wonderful job they are trying to convert the issue by saying that the State Government has said or a statement was made by the Chief Minister to the effect that State had not got any information from the Central Government, without looking into what was the statement and what was the question which was put by the press. If the press puts a quaestion whether you had information with respect to the planning of terrorist attack in the courts, the answer was 'no, we had not received any such information from the Central Government.' Now, whatever information comes, that is always taken care of and immediately, action is taken. Both the Central Government and the State Government, not only the State of U.P., I am sure, all the States of the country, are always in touch with each other, and coordinate with each other, and that is how the situation is handled. As was pointed out by some Members, this is the largest State having 18 crores of people and an incident has taken place inside the court premises for which, the reasons have been given in the e-mail as to why they did so. That is to be looked into. It is a bigger thing which has to be considered, and after considering that, it has to be found how to solve that. We should unitedly think how to control this menace. My senior learned colleague, Mr. Joshi, said that he has knowledge of certain terrorists camps and certain terrorist activities happening in his own district. If he has certain information, it could be furnished. Action will be taken. Whatever information he has it could be divulged, and I am sure that action will immediately be taken by the Central Government and the State

Government against all concerned persons. Of course, up till now, an incident like this was happening in temples, but now it has happened in the temple of courts. And as rightly said, the intention of the terrorists is to see that the courts also are terrorised and the judicial actions being taken therein are disturbed. This is a serious thing, and this is what is to be considered. So far as the State Government is concerned, the State Government has already informed the Committee; the Central Government has already made a statement-which has been circulated here-that the State Government has taken notice of it, and it has taken all the precautions. So far as the courts are concerned, we have to understand one thing that the jurisdiction of the courts with the High Court. State Government provides whatever security is required, and which is thought should be provided, but it is to be provided with the consent of the Chief Justice or the concerned court. Immediately after this incident, the security has been beefed up in all the district courts and the High Court. And a letter has also been written to the High Court for seeking their permission so that police can enter into the premises and put more police strength so far as courts are concerned. But it is not only in the courts but also in other places that the security has been beefed up by the State Government, and steps are being taken to see that such incidents do not happen again. And as rightly said by Shri Sharad Yadav, the manner in which this incident has taken place is such that it is very difficult to tackle under if some information is there that some activity at some place is going to take place. Despite that, whatever best possible measures for taking precautions can be taken are being taken, and will be taken by UP State Government. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Mr. Misra. Now, Shri Ravula Chandra Sekar Reddy;

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I will take one second. I just want to ask my colleague that if Government was so serious, if they knew about it, and if the Centre had given them the information.....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, no. Why should you ask your colleague? You can put a question only to the Minister.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sorry. Through you, Sir, I am asking. ...(*Interruptions*)... can am I ask through you Sir?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no; you cannot put a question to your colleague like this.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Pardon me, Sir?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You can put it to the Minister; otherwise, I will give you time. Then, you can ask.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sorry. Which Minister?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I will give you time and, then, you can ask. ...(*Interruptions*)...

AN HON. MEMBER: The Parliamentary Affairs Minister is there. You can ask him. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You can ask the Minister...(*Interruptions*)...

**2.00 P.M.**

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: If they were so serious, and if the information was being given by the Centre that there was some terrorist activity going on, in a very, very large measure, in Uttar Pradesh, how can the Chief Minister and the other Ministers of a State go out? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, no. That is okay.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: How can they go out when such a serious incident has happened? ...(*Interruptions*)...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: My statement is wrongly looked into, Sir.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, how can the Minister go out when such a serious incident has happened, to do political activities? I Just want to ask this.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is okay. That is enough. ...(*Interruptions*)... Shri Ravula Chandra Sekar Reddy. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: This shows how serious you are!

THE VICE-CHAIRMAN (PFOF. P.J. KURIEN): If you want to make a point, you will be given time later. But there is no need to interrupt like this. ...(*Interruptions*)... I thought, you are going to put a question to the Minister, but you are putting it to your colleague.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I, on my own behalf, and also on behalf of my party, TDP, strongly condemn the ghastly incidents in Lucknow, Varanasi and Faizabad, in which 13 people were killed and 80 persons were injured. In fact, my leader Chandra Babu Naidu, along with the UNPA leaders Shri Mulayam Singh Yadav and Shri Amar Singh, visited yesterday the places affected by the blasts, tried to console the people and expressed his sorrow. I would like to remind this august House, Sir, of the bomb blasts which took place in Hyderabad, in August, in which 44 persons were killed in Lumbini Park, Gokulchat, and 54 were injured on that night, and prior to that, in the historical Mecca Masjid, 14 people were killed and 54 were injured during that incident. Sir, serious incidents are taking place in the country in States like Karnataka, Rajasthan, Maharashtra and Delhi. I request the Government of the day to protect the lives and properties of the people. I request the Government to take urgent steps for protecting the lives and properties of the people so that such incidents will not occur in future, and create confidence among the countrymen. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you very much, Ravulaji, for being brief and concise. Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Thank you, Sir. At the outset, my party, the Communist Party of India, joins the entire House in condemning the serial bomb blasts that took place in Uttar Pradesh. While agreeing with the statement made by the Home Ministry, I would like to raise some issues for consideration. I find that there is a need to streamline our intelligence network and strengthen our intelligence agencies because there is a failure of intelligence agencies to investigate and pre-empt. ...(*Interruptions*)... May I continue after lunch break? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No. You pleased proceed. No prblem. You will proceed. ...(*Interruptions*)... After D. Raja, you will be called.

SHRI D. RAJA: Sir, the one area that the Government will have to ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No. This is an important discussion. Don't make disturbances. It is a very important discussion. There are a number of hon. Members to speak ...(*Interruptions*)...

SHRI DINESH TRIVEDI (West Bengal): Members are not present in the House. It was not announced earlier. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No. Who are not present? ...(*Interruptions*)...

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA (Rajasthan): Sir, you take the sense of the House so that there would not be any violation of the procedure. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTINGS (SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI): Sir, a decision was taken at the meeting of the senior leaders that there would be no lunch break. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It has already been agreed to that there would be no lunch break. Not only that it is an important discussion, but also more than a dozen hon. Members want to sepak. I want to give time to every one. The less you speak, the better. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, you please take the sense of the House. ...(*Interruptions*)...

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: That is what I am saying. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Raja, you please proceed. ...(*Interruptions*)...

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Mr. Vice-Chairman, Sir, the procedure is that whatever decision that has taken place in the Chamber has to be announced in the House because Members don't know whether there is going to be a lunch break. So, you announce it and take the sense of the House. This is the procedure. ...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): We can even compensate by extending the sitting. ...(*Interruptions*)... We can exend our sitting so that we can compensate. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Let me finish. ...(*Interruptions*)...

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: I am only saying that the procedure should be followed. That is it. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI: Sir, I think what Najmaji is saying is correct. Najmaji has correctly advised that it should be announced in the House. But we agreed to it in a situation when the House was in turmoil and got adjourned. Then it was decided (a) the Chair will make a note of condolence, (b) instant statement by the Home Minister, and (c) instant debate. Since it was no expected—the most important business today is Karnataka Presidential Proclamation; it has to be ratified today—it was agreed in the presence of senior leaders—my colleagues were there—that the House would proceed without lunch break. Then

somebody said, "Lunch break means that the hon. Minister has to feed them". That is a different issue. But the factual position is that a decision was taken and the issue was resolved. If there is any communication gap in announcing it instantly by the Chair, I can't question the Chair's wisdom. But, on behalf of the Government, I can say, "Yes, the Parliamentary Affairs Minister should have stated this instantly". I promise, Najmaji, that this kind of departure shall not take place, as you have rightly pointed out.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): In view of the explanation of the hon. Minister, I hope the House will agree.

SOME HON. MEMBERS: Yes

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We will continue with the discussion.

SHRI D. RAJA: Sir, I resume my intervention. The intelligence is one area the Government will have to look into. There are many bomb blasts that have taken place. We get agitated and we get, sometimes, very numb and immune. This is in no way good to tackle the problem of terrorism because the *modus operandi* of terrorists needs to be investigated properly. After every bomb blast, the Governemnt comes out with a report saying one or two bombs remained unexploded. And this is an issue and the Government will have to seriously look into this. Like, what the *modus operandi* is, how some bombs get blasted and some bombs remain unexploded. There is some hi-tech involved and the intelligence agencies must be equipped to tackle this hi-tech used by terrorists. There should be cameras in public places. In some Government offices and some banks, we have cameras to monitor the movements of people. I feel, even in airports, bus stands, railway stations and such other public places, there is a need to have cameras to monitor the situation becuase terrorists are using hi-tech devices and through e-mails, etc. they carry out their activities. If our intelligence agencies are not equipped in this regard, we will be facing similar problems in the coming days. Some years back, our Government agreed to set up an office of FBI. But I do not know what is happening and what it means because our level of intelligence is not adequate to face the situation. That is the point which I am making. Then, I agree with the Home Ministry that we will have to fight terrorism unitedly with a resolve, with a determination, to maintain harmony. Here, we must also keep in mind the fact that our counry is a State of tremendous diversities. All sections of our population should have a sense of security to live in this country. If that is disturbed, then, we will be facing a lot of problems in the coming days. Moreover, after the U.S. waged war against Iraq, it was clear that imperialism identified terrorism with one religion. India, being home for all religions, you cannot afford to identify any particular religion with terrorism. We should realise that there are extreme communal forces in all religions which try to disrupt the harmony, disrupt the unity and integrity of the country. And, I must say, the majority communalism or minority communalism feed each other, and we will have to condemn the communal extremism, communal fascism of every kind, every brand and every shape. It is a threat to the unity and harmony of our people, of our country.

Here, I must also make a point that some people, including the main Opposition party, demand that POTA should be brought back or POTA should be suitably amended. But our experience has been different and horrible. The POTA or TADA were all used to terrorise innocent people and that is why there was a resistance to all these Acts and, finally, we had to get rid of the Acts. It is of no use arguing now to bring back these Acts. But the existing laws must be used effectively to fight the menace of terrorism. There must be a political will;

there must be a determination; there must be a resolve on the part of the political parties as well as the Government to isolate the terrorist forces, the extremist forces, and unite the people in this struggle against terrorism. This is what, as the CPI representative, I would like to bring to the notice of this august House.

Finally, Sir, there must be coordination between the State Governments and the Central Government, and the level of coordination must improve; it must be raised because now nobody should try to blame each other. But it is a failure, and this failure has to be taken up collectively by the Governments, and that is where the need for an effective coordination between the State Governments and the Central Government is essential. I hope, in the coming days, we will act in this regard in a fitting manner. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Ram Jethmalani....*(Interruptions)*

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, where is the Minister?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) There are three Cabinet Ministers and two or three State Ministers, including the Minister of State for Home Affairs, sitting here. There is enough number of Ministers... *(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, morning itself, this issue was raised... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It is a collective responsibility, Kindly take your seat... *(Interruptions)*...

SHRI AMAR SINGH: Sir, you mentioned the collective responsiblity of the Cabinet. Mr. Dasmunsi said one thing and Shri Shivraj Patil said something else on Nandigram. Then, why are you talking about collective responsibility?

THE VICE- CHAIRMAN (PROF P.J. KURIEN): It is the collective responsibility in a parliamentary democracy. *(Interruptions)*

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The idea is not to interrupt the debate, Sir. Let me bring it to the notice of the Chair and the House also that there was a feeling that when such sensitive issues are discussed, the concerned Minister should be present. The rule, of course, is that one Minister can take notes for all. But then, why is there this entire Cabinet and all others? The point is that we are discussing such a sensitive issue; the entire country is looking towards us. Fortunately, there is peace also in the House. A meaningful debate is going on. It was assured to us in the morning that the Home Minister, Shivraj Patilji will come here. He has not come. And the other Minister has also gone. He is coming in just now. *(Interruptions)*

THE VICE- CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You know, there are two Ministers of State in the Ministry of Home Affairs here, three Cabinet Ministers.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Cabinet Ministers are not noting, Sir. The concerned Minister should be there. *(Interruptions)* Then, what about the Cabinet Minister? They said he is in Lok Sabha. Is the Lok Sabha also discussing the same issue?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You were in the Government. You know these problems. If anyone else had raised it, I would have understood.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Yes, Sir; and I used to be there in the Hosue. *(Interruptions)* When debates and discussions are going on here, some Ministers are sitting and watching

cricket match at Feroze Shah Kotla grounds. *(Interruptions)* I thought when a senior member like Shri Ram Jethmalani was speaking, there should be some senior Minister present in the House.

SHRI RAM JETHMALANI (Nominated): Sir, I have very special affection for Mr. Shivraj Patil. I am very happy that we unanimously approved the Chair's Resolution this morning which adequately conveys the contempt of the Indian nation for the horrendous crimes of the perpetrators of these acts of terrorism in three of our cities. At the same at those who have lost their lives, those who are living but some of them in a critical condition, and of course, their kith and kin who have suffered untold and undeserved misery.

But the question is: after having passed this Resolution and sought some clarifications from the Government, does the duty of this House come to an end? Do we, after having done this job today in another one hour of the House, go back to our small power games, toppling tricks, unholy compromises and criminal cover-ups?

Sir, there are a few matters which arise out of the statement. And since you have advised us to confine ourselves to clarification of issues, the first point that I wish to ask is that, when this statement, at more than one place, characterises the happenings as acts of terrorism, I hope it is realised by the Government that terrorism is not a subject of law and order. The Supreme Court in its solemn judgment has held that terrorism, of both kinds, whether internal or external, is an an assault on the sovereighty and defence of India and, therefore, is primarily a Central Subject. Being a Central Subject, Sir, it is the primary duty of the Central Government to see to it that these offences do not take place or, at least, recur with the frequency with which they are now occurring and that they are adequately investigated and those found responsible for these acts punished so that there should be some deterrence.

I regret, Sir, that the statement does not show this realisation. What is said, for example, in the fifth paragraph is, "Investigations into these blasts have been given to the Special Task Force by the State Government. The Central Agencies are also helping the State Police in this regard".

Sir, this is a reversal of roles. The primary responsibility for acts of terrorism and to investigate them is that of the Centre. You are seeking and you are entitled to seek the cooperation of the State Government. If it gives that cooperation to you, it is perfectly all right, it is redound to the credit of the State Government. But please do not by this jettison your primary responsibility because we are dealing with not a State subject, but with a Central subject.

Then, Sir, I do wish very seriously not to succumb to the temptation of scoring any brownie points against anybody. I have not such motivation. But, Sir, even if you detect a failure somewhere, a failure in some quarter, a failure which amounts to terrible neglect or jettisoning of duty, yet we must recognise that in a sense it is the collective failure of all of us, and, therefore, we have to put forth and put across a pool or our collective experience, our collective knowledge, collective intelligence, collective techniques and collective influence wherever that influence can bring about a change of motivation for these acts of terrorism.

Sir, another thing which requires a serious consideration is,—and I had raised that subject the other day when the Question Hour was going on—I said, all terrorism is not of

the same kind, motivations are different. Some terrorism is purely political and territorial of the kind which we encounter, for example, in the State of Jammu and Kashmir. But, Sir, there is another terrorism in which the motivation is totally different. My friend, Raja is right and that is why, Sir, I have so much respect for him, in spite of our differences on some points, when he said that no religion has to be identified or associated with any acts of terrorism, perfectly right. But, Sir, I don't do it as a matter of political strategy. I do it as a matter of my understanding of religion. There is no religion in the world which advocates or sanctifies terrorism, and those people who go about telling others that your religion requires you to indulge in acts of terrorism, they themselves are terrorists and must be dealt with in that particular manner. But, Sir, there is no doubt that some misunderstanding of religion is also in some cases the motivation for acts of terrorism. And, Sir, there, you cannot treat it as a law and order problem: you cannot treat it as a purely punishing problems of criminal law or creating deterrence, you have to address yourself to the mind of the people, to the brain of the people, to their understanding of things, and, Sir, a dialogue is called for with these people and more than anything else, Sir, what is called the need for secular education in India. Sir, I have been writing about it times out of number that India has failed, while proclaiming secularism, failed to give secular education throughout the country. And, Sir, secularism has got to be taught. And, Sir, I mean, no disrespect to anybody, I am speaking with great humility and with great anguish almost that those who beat their breasts and all the time talk about secularism have not understood even the 's' of secularism what secularism requires. Sir, the first thing which secularism requires and that is a matter where we have to go round and create a new culture is, what used to happen in the court of emperor Akbar. The Nine Jewels of the court used to sit, discuss religious doctrines, criticise each other's doctrine, show the superiority of one doctrine over another, but nobody got up and stabbed anybody, and nobody out of anger got so provoked that he indulged in acts of terrorism. Sir, when we can peacefully and in a spirit of understanding and a spirit of enlightenment sit and discuss religious doctrines and subject them to the rule of reason, that is secularism. But, unfortunately that secularism is not being taught, is not being even advocated. However, Sir, some day, I hope, it will be done.

Sir, the response to these acts is childish, "We have given Rs. 5 lakhs to those who are dead and Rs. 1 lakh to those who have been injured". Sir, these are all childish responses to this very, very horrendous activity. "We have not said that you must create more vigilance in other district courts. " The terrorists know it. Now that they have attacked courts, they know that you will be more vigilant at some other courts and they will not attack your courts at least for some time until you gorforget this. I must tell you, it is pathetic.

Sir, last night I was sitting before the TV and I happen to see only for a few minutes because I could not afford to sit and listen to the whole thing. There was some gentleman who probably had something to do with our R&AW and intelligence agencies. He was on TV and explaining why our efforts to curb terrorism have failed. One of the things which I heard from him and which made me very angry about what is happening is when he said that terrorists have now changed their techniques! One of the illustrations he gave is, previously terrorists were using telephone for their communication and now they were using couriers. Do we not have this much intelligence that naturally the terrorists will go no changing their techniques and technologies? This is not an adequate explanation.

Sir, I must say that the problem of terrorism is that these acts take place without notice. How do we manage to get notice? Sir, I should not even be discussing these matters in the

House; I wish the Minister in-charge of it at least have the decency and the humility to call important Members of the House and sit with them in private and try to understand this problem. Sir, let me summarise in one word. The problem of terrorism and its conquest is the problem of infiltration into criminal organisations. There are many people who have tremendous experience of how to infiltrate into other organisations.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: He has the experience of all parties!

SHRI RAM JETHMALANI: My friend Raja is laughing... *(Interruptions)*... We should use the collective experience of the past, infiltrate into organisations; otherwise, you will never know when that organisation is going to hit and where it is going to hit and by what technology it is going to hit. Sir, these are the things which have to be learnt and I regret to say that this is not sufficiently appreciated, this does not show adequate response.

There is one last thing. Again, I wish to express my agreement with my friend, Sitaram Yechury. He is very angry with me that I have been opposing him on some other points of great importance. But, Sir, I agree with him that Taslima and Hussain must be dealth with in the same way. But it is a disgrace to our judicial system, it is a disgrace to our political system that Hussain has to live in Dubai as an outlaw, but it is equally a disgrace to our hospitality, our civilisation that a poor woman who is almost seeking refuge from persecution in her own country is being asked to get out. Both must be treated alike. Both must be brought back here and treated as our honoured guests and given complete security and safety. That is what the society requires and that is what the greatness of India requires. Thank you.

**श्री विनय कटियार:** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हम चाहते थे कि प्रश्न काल के समय ही इसकी चर्चा आरम्भ कर दी जाती, लेकिन प्रश्न काल हो नहीं सका और उसके कारण सदन स्थगित हो गया।

यह आतंकवाद आज देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। आए दिन देश के अन्दर हर जगह आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। आज हमारे देश के अन्दर आतंकवादी योजना बना रहे हैं। किसको मारना है, आतंकवादी योजना बना रहे हैं। कब मारना है, आतंकवादी योजना बना रहे हैं। कहां मारना है, आतंकवादी योजना बना रहे हैं। कैसे मारना है, आतंकवादी योजना बना रहे हैं। श्री के॰पी॰एस॰ गिल ने एक पुस्तक में लिखा है कि इस आतंकवाद के चलते आतंकवादियों के द्वारा 40 हजार से भी अधिक लोग मारे गए हैं। इस देश के अन्दर यह कोई छोटी संख्या नहीं है, बड़ी भारी संख्या है। जब वह यह पुस्तक लिख रहे होंगे, उस समय से लेकर आज तक अगर उसका पूरा आंकड़ा लगाया जाए, तो यह बड़ा भारी नम्बर है। बहुत सारे लोक आतंकवाद के शिकार हो गए। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो लोग मारे जा रहे हैं, उनका दोष क्या है? क्या वे जीना नहीं चाहते? क्या इस देश के साथ उनका प्रेम नहीं है? जो लोग मारे जा रहे हैं, उनकी पत्नियों का सिन्दूर उजड़ रहा है। बच्चे भी मारे जा रहे हैं। उन माताओं की गोद सूनी हो रही है। जेठमलानी जी ठीक कह रहे थे कि हम थोड़ी चर्चा करके इसको खत्म कर देंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, तो जिन लोगों ने मारा, उनकी वकालत किसने की? हमारे इस देश के अन्दर जो आतंकवादी हैं, जो ये घटनाएं कर रहे हैं, जो रक्त बहा रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, आज उनके बचाव में हमारे देश के कुछ जाने-माने लोग प्रतिष्ठित लोग, वकील लोग अगर उनकी पैरवी में खड़े हो जाएंगे, तो आतंकवाद कैसे रुकेगा? वह रुक नहीं सकता... (व्यवधान)... आज स्थिति यह बन गई है—हमारे लोग कह रहे हैं कि इनके कारण से हमारे 2-2 प्रधान मंत्री चले गए। अभी जब राजीव शुक्ल जी बोल रहे थे—मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि आतंकवाद जन्मा कैसे, मैं उस विस्तार में जाना नहीं चाहता... (व्यवधान)...

SHRI N. JOTHI: Sir, he is not a lawyer... *(Interruptions)*... No lawyer can refuse... *(Interruptions)*.....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is not yielding. ...(*Interruptions*)...

SHRI SHAHID SIDDIQUI: It is a Fundamental Right in our Constitution. ...(*Interruptions*)...

**श्री विनय कटियार:** आप मुझे फंडामेंटल मत बताओ ...(**व्यवधान**)... मुझे सब मालूम है। फंडा में डंडा होने वाला है, इसकी व्यवस्था करो ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KUIENE): You can reply when your turn comes. ...(*Interruptions*)... Mr. Siddiqui, your name is here, you can reply. ....(*Interruptions*)...

**श्री विनय कटियार:** आप हमें फंडा बता रहे हो! ...(**व्यवधान**)... हाउस के चलते हुए विस्फोट हो रहा है ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Vinay Katiyar, please address the Chair. ...(*Interruptions*)...

**श्री विनय कटियार:** इसलिए माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं किसी के नाम की बात नहीं कह रहा हूं। सवाल यह उठ रहा है ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You are expressing your opinion. We will listen to it. ...(*Interruptions*)...

**श्री विनय कटियार:** मैं अभी तक शांत बैठा रहा। हमें कहा गया था कि आप केवल उत्तर प्रदेश पर बोलें, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सब पूरे देश पर बोल रहे हैं, तो इसलिए मुझे उधर तक जाना पड़ा, नहीं तो मैं केवल उत्तर प्रदेश तक रहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)... नहीं, फैजाबाद है, लखनऊ है, बनारस है–मैं पूरे उत्तर प्रदेश तक ही रहना चाहता हूं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जब हमारी सरकार को हमारे देश के अन्दर कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इसकी जानकारी नहीं है...(**व्यवधान**)... मैं उधर ही आ रहा हूं। वे हमारे मित्र हैं, इसलिए अच्छा है, भगवान करे कि वे बड़े नेता बन जाए।... हमारे देश के अन्दर बांग्लादेश के कितने घुसपैठिए हैं, अगर हमारी सरकार को यह नहीं मालूम है, तो इससे दुखद आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। अमेरिका के अन्दर एक घटना घटित हो जाती है, तो जीरो टॉलरेंस वहां नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं किया जाता है और हमारे यहां, इस देश के अन्दर, आए दिन कहीं-न-कहीं आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। बनारस में दो सालों के अन्दर यह चौथी बार है। चौथी बार घटना हुई है। राजीव शुक्ला जी, क्या आप को मालूम नहीं, इस देश में आतंकवाद, राजनीतिक दल, उनकी कोख से पैदा हुआ है, उनकी नीतियों से पैदा हुआ है। महोदय, लिट्टे को किस ने बढ़ाया? मैं उस ओर नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन जब हम आतंकवाद पर चर्चा करते हैं तो हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा।

THE VICE-CHIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Vinay Katiyar, please listen. You are supposed to seek clarifications on the statement. If you are going to make a big speech, there is no time... (*Interruptions*)... Please, confine to the statement. Please confine to the statement... (*Interruptions*)... You please sit down. You are not called... (*Interruptions*)... You please sit down. Mr. Pany, please sit down. Please confine to the statement... (*Interruptions*)...

**श्री विनय कटियार:** उपसभाध्यक्ष जी, आप की बात को पूरी तरह से शिरोधार्य करता हूं, लेकिन मुझे आप का संरक्षण चाहिए। महोदय, मैं एक बार और बोला था और आज दूसरी बार आप की अनुमति से खड़ा हूं।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन):** आप को पूरा प्रोटेक्शन है, लेकिन टाइम की बात है।

**श्री विनय कटियार:** महोदय, मेरे लिए टाइम की बात कह रहे हैं, लेकिन जिनका एक सदस्य है, उनके लिए no time. कौनसा टाइम? महोदय, जिस ने पहले नोटिस दी है, सुबह साढ़े 9 बजे आकर नोटिस दी कि इस विषय पर ध्यानाकर्षण स्थगित करके चर्चा कराई जाए, उसे इतनी देर बाद नंबर दे रहे हैं। महोदय, मैं उसे चैलेंज नहीं करना चाहता।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Vinayji, I was only cautioning you. I did ask you to stop. I was only cautioning you. You please conclude in ten minutes... (*Interruptions*)...

**श्री विनय कटियार:** उपसभाध्यक्ष जी, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आप की बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मुझे बोलने तो दीजिए। मैंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा, मैंने तो इतना याद दिलाया कि ''लिट्टे'' को किसने खड़ा किया? मैंने राजीव शुक्ल जी को याद कराया कि भिंडरावाले को किसने खड़ा किया? मैं यह याद करा रहा हूं कि आसाम के अंदर ''उल्फा'' के साथ मिलकर चुनाव किसने लड़ा? आंध्र प्रदेश के अंदर मिलकर चुनाव किसने लड़ा? केरल में मदनी के साथ समझौता किसने किया? फिर आप कहते हैं कि उस को बोलो नहीं, तो उत्तर प्रदेश तक कहां सीमित रहेंगे?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, you address the Chair. ... (**व्यवधान**)... बैठिए। Don't disturb.

**श्री विनय कटियार:** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, 23 फरवरी, 2005 को दशाश्वमेघ घाट पर हमला हुआ जिस में 7 लोग मरे और काफी घायल हुए। 28 फरवरी को विश्वनाथ मंदिर के पास विस्फोटक पदार्थ मिला। 7 मार्च, 2005 को कैंट स्टेशन और संकटमोचन मंदिर, वाराणसी में मरने वालों की संख्या 18 हुई और 50 से अधिक लोग घायल हुए। 23 नवम्बर, 2007 की घटना, जिस के कारण यह चर्चा हो रही है, कचहरी परिसर में दो स्थानों पर 9 लोगों की हत्या हुई और 50 से अधिक लोग घायल हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो रहा है। वहां एक महिला कबीर चौराहा, शिवप्रताप हॉस्पिटल में भर्ती है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी और हम सब लोग उन तीनों स्थानों पर गए थे। वह महिला हमारे सामने रो रही थी कि उसका इलाज नहीं हो रहा है। मैंने श्री सतीश चन्द्र मिश्र जी से आग्रह किया कि उस की जांच करवा लें और न हो तो उसकी व्यवस्था करवा दें।

**श्री सतीश चन्द्र मिश्र:** मैंने तुरंत पता लगवाया और उसका पूरा इलाज हुआ है।

**श्री विनय कटियार:** धन्यवाद। महोदय, फैजाबाद में 5 जुलाई, 2005 को राम जन्म भूमि पर हमला होता है और आतंकवादी मारे जाते हैं। गुजरात की सरकार पुलिस नौजवानों को पैसा भेजती है। उनको पैसा नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? इसमें भेदभाव क्यों होता है? अगर कोई पुलिस का जवान बहादुरी के साथ आतंकवादियों से लड़ता है, राज्य सरकार उसको पुरस्कार देती है और अगर दूसरे राज्यों की सरकार उनको पुरस्कार देना चाहती है, तो उसमें भेदभाव क्यों? वहां लोग मरे, उनके लिए हमारी दो-तीन राज्य सरकारों ने वहां पैसा भेजा, मगर वह पैसा उन पीड़ित परिवारों को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर 5 जुलाई, 2005 की घटना होती है और 10 जुलाई, 2005 को, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरी हत्या करने के लिए कैंटोनमेंट में, छावनी में आते हैं, तीन लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर आगे के लिए कुछ सोचा नहीं जाता। यह 23 नवंबर को घटना हो गई। अयोध्या के अंदर कई बार रेलवे स्टेशन पर विस्फोटक सामग्री मिली, पहले लखनऊ में जो तीन आतंकवादी पकड़े गए थे, वे फरार हो गए, अदालत से भाग गए, पुलिस की कस्टडी से भाग गए। यह कैसी लचर व्यवस्था है? आतंकवादी, सीरियल आतंकवादी पकड़े जाते हैं और कचहरी के अंदर से भाग जाते हैं, इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, एजेन्सियों पर सवाल उठाया जाता है। हम कहते हैं, ईमानदारी से इस पर विचार करना चाहिए कि क्या यह बात सही नहीं है कि एजन्सी के लोग दिल्ली में भारत सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं और दो-दो महीने तक हमारे संबंधित विभाग के मिनिस्टर को फुरसत नहीं होती कि रिपोर्ट जो आई है, उसको पढ़ा जाए? आज के समय में राजनेताओं को बाकी दस कामों में फुरसत हो रही है, मगर देश के अंदर आतंकवाद बढ़ रहा है, खुफिया एजेन्सियां रिपोर्ट दे रही हैं, ...(**व्यवधान**)

**उपसभाध्यक्ष (पो० पी० जे० कुरियन):** आप जल्दी कनक्ल्यूड कीजिए। बारह स्पीकर्स का नाम और आ गया है। ...(**व्यवधान**)... There are one dozen speakers. You have taken the maximum time—13 minutes.

**श्री विनय कटियार:** सर, मैं जल्दी कर रहा हूं। जिन्होंने सबसे पहले नोटिस दिया, उनको सबसे बाद में मौका मिल रहा है। उपसभाध्यक्ष जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं तो अभी कम बोल रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): There are more than a dozen speakers. कनक्ल्यूड कीजिए। You seek only clarifications ...(*Interruptions*)... Why speech?... (*Interruptions*)...

**श्री विनय कटियार:** सर, मैं कह रहा था, हमारे संबंधित मंत्रियों को उनकी रिपोर्ट को पढ़ने का समय नहीं मिलता। अगर घटना होती है, तो हमारे एक मिनिस्टर टी०वी० पर जाकर कह देते हैं, जहां-जहां घटना होती है, कि हमने तो पहले बता दिया था।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now you, seek clarifications ...(*Interruptions*)... Now, you come to clarifications ...(*Interruptions*)...

**श्री विनय कटियार:** हमने पहले बता दिया था। यदि बता दिया था, तो फोर्स क्यों नहीं भेजी? ...(**व्यवधान**)... मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि उधर से जवाब आना चाहिए। इसमें तय हुआ था कि माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित रहेंगे। आज माननीय गृह मंत्री जी यहां पर आए नहीं, शायद प्रियरंजन दास जी ने उनको बताया नहीं। ...(**व्यवधान**)... आप बता रहे हैं कि नोट कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, मेरा कहना है कि आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, उसका किसी धर्म से कोई नाता या रिश्ता नहीं होता। ...(**व्यवधान**)... मैं हमेशा रास्ते पर हूं, लेकिन आप बेरास्ते हो जाते हो, भटक जाते हो और वोट के कारण भटक जाते हो। अगर वोट के कारण न भटका जाए, तो देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने में देर नहीं लगेगी। ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन):** आपके 14 मिनट हो गए, अब काप कनक्ल्यूड कीजिए।

**श्री विनय कटियार:** सर, यह इतनी बार कहा जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन):** मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया है।

**श्री विनय कटियार:** यह जो गुप्तचर एजेन्सी पर बार-बार आरोप लगाया जा रहा है, एक सरकार दूसरी सरकार पर आरोप लगा रही है, यह उसका सही समय नहीं है। इस आतंकवाद से निपटने के लिए पूरे देश को संकल्प करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा और आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि पोटा कानून मत लाओ, लेकिन पोटा जैसा अगर कोई दूसरा कानून आप बनाना चाहते हो, उसे आप लाइए, हम आपका, भारतीय जनता पार्टी दोनों सदनों में आपका समर्थन करेगी, लेकिन यह ऐसे लच्. कानून से नहीं चलेगा, केवल जो सटीक उत्तर है, उसको कहने से काम नहीं चलेगा, केवल सीमा पर मोमबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा। इन आतंकवादियों ने जो खून बहाया है, अफजल गुरू को जैसे अदालत से फांसी दी गई, तो उसका पालन इस सरकार को कराना चाहिए। जब तक आप इस प्रकार के आदेशों का पालन नहीं कराएंगे, तब तक अदालतों पर भी हमले बढ़ेंगे। सामान्य नागरिक मारे जाएंगे, वकील भी मारे जाएंगे। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि चर्चा तो इस पर लंबी होनी चाहिए, बाकी सदस्य तो दूसरे राज्यों पर चले गए, मुझे बोलने दिया जाए।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन):** आप खत्म कीजिए।

**श्री विनय कटियार:** ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री तारिक अनवर** (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जो निन्दा प्रस्ताव पेश किया गया है, जो मृतक परिवार हैं और जो जख्मी हुए हैं, उनके प्रति सदन में जो संवेदना प्रस्तुत की गई है, उससे मैं स्वयं को भी और अपनी पार्टी–राष्ट्रवादी कांग्रेस पाटी की भावना को भी उसके साथ जोड़ते हुए, जो घटना घटी है, उसको condemn करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं।

अभी गृह मंत्री जी ने जो बातें बताई पूरी घटना के बारे में, यह जरुर चिंता का विषय है। आज आतंकवाद सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बना हुआ है और उस परिस्थिति में खासकर भारत में, राष्ट्र में इस समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या समझना चाहिए। जैसा हमारे और माननीय सदस्यों ने कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसको एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेकर इसका समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। यह बात सही कही गई, जैसे श्री सीताराम येचुरी जी ने और दूसरे लोगों ने भी यह कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं उसकी कोई जाति नहीं होती, आतंकवाद आतंकवाद है। अगर यह कहा जाता है कि यह हिन्दू आतंकवाद है, यह आतंकवाद है, तो यह गलत है या किसी भी धर्म से उसको जोड़ा जाए, तो वह गलत है। आतंकवाद की एक

ही परिभाषा है कि वह किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए एक खतरा है और उसका मुकाबला संयुक्त रूप से करना चाहिए, जो गृह मंत्री जी ने भी कहा है और हम भी इस बात से सहमत हैं कि जहां तक पुलिस की भूमिका है, सूचना तंत्र की भूमिका है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स की भूमिका है, इन तमाम चीजों को जोड़कर देखना चाहिए और किस तरह से हम इस आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, इसको देखने और समझने की जरूरत है। इस बात पर यहां विचार रखा गया है कि सूचना तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, मैं भी चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें और किस तरीके से राज्य और केन्द्र में समन्वय हो सके, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें राज्य और केन्द्र में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में समन्वय, co-ordination की अति आवश्यकता है।

**[श्री उपसभापति पीठासीन हुए]**

उपसभापति महोदय, मैं यह भी मानता हूं, जो अभी कहा गया innocent लोगों को सताने के बारे में। यह बात भी सही है कि पुलिस अपनी कमियों को दूर करने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए कभी-कभी बेकसूर लोगों को मुकदमे में फंसा देती है, उनके नाम पर खानापूर्ति की जाती है, ताकि पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बच जाए और लोगों को यह कह सके कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, कुसूरवार हैं, उनको हमने पकड़ लिया, लेकिन सच्चाई यह होती है कि कभी-कभी बहुत ही innocent लोग, जिनका घटना से कहीं कोई संबंध नहीं होता, वैसे लोगों के नाम भी डाले जाते हैं, उनके परिवार के लोगों को भी परेशान किया जाता है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री अबू आसिम आज़मी** (उत्तर प्रदेश): महाराष्ट्र में तो ऐसे ही होता है।

†[شری ابو عاصم اعظمی : مہاراشٹر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔]

**श्री तारिक अनवर**: महाराष्ट्र में ही नहीं, किसी भी राज्य में अगर यह होता है तो मैं उसको गलत मानता हूं। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं, आप दलगत राजनीति में पड़कर बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना दिमाग ऊपर कीजिए। ...**(व्यवधान)**... आपने चूंकि महाराष्ट्र का नाम लिया, इसलिए मैं कह रहा था, आप पूरे देश को सामने रखकर बात करिए।

उपसभापति जी, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करूंगा, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो दूसरे लोगों ने यहां बातें कहीं, जो सुझाव रखा, इसकी जरूरत है, इसकी आवश्यकता है कि किस तरह से आतंकवाद पर अंकुश लगाया जाए, कैसे इसको रोका जाए। जैसा मैंने शुरू में कहा कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसे हम सबको हल करना चाहिए। अपने स्टेटमेंट के आठवें पैराग्राफ में जैसे गृह मंत्री जी ने कहा है कि इसमें हम political parties, civil society, media and the public at large, इन सबका समावेश चाहते हैं, सबका समर्थन चाहते है, सबका सहयोग चाहते हैं और हम भी यह जानते हैं कि जब तक सबका समर्थन और सहयोग नहीं होगा, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी विस्तार से सदन को इस बात की जानकारी दें कि किस तरह से हम आने वाले समय में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने सूचना तंत्र को, अपनी पुलिस को और खास तौर पर राज्य और केन्द्र सरकार के बीच में जो समन्वय है, उसको कैसे मजबूत करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

**श्री महमूद ए॰ मदनी** (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं। सब लोगों ने इसकी मज़म्मत की है और करनी चाहिए, तो मैं भी वहीं से शुरू करता हूं। ये जो हादसात हुए हैं, सिर्फ अभी के नहीं, शुरू से जो होते चले आ रहे हैं, ये मुल्क के लिए निहायत अफसोसनाक और काबिले-मज़म्मत हैं। मुझे इस मौके पर एक शेर याद आ रहा है कि–

> "किसी के दर्द और गम को, किसी का नाज़ क्या जाने,
> गुज़रती सैद पर क्या है, दिले सय्याद क्या जाने।"

शिकार पर क्या गुजर रही है, यह शिकारी को क्या खबर? मैं यहां बात कर रहा हूं कि जिस दिन यह बनारस का हादसा हुआ, इन तीनों जगहों का, शाम को साढ़े सात बजे की फ्लाइट से मैं बनारस पहुंचा। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, तो मुझे लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थोड़ी देर पहले वहां पहुंची हैं। वहां एक कान्फ्रेंस थी, हम लोग वहां पहुंचे, कान्फ्रेंस बिल्कुल educative conference थी, जिसका politics से, regional politics से कोई मतलब नहीं था, लेकिन कान्फ्रेंस के organisers और सब लोग यही कह रहे थे कि आज जो incident हुआ

है, इसकी मज़म्मत होनी चाहिए और इसी बात पर होनी चाहिए। मैं वह mentality बताना चाहता हूं कि चूंकि वहां मुसलमान जमा थे, तो उनको यह चिंता थी कि आज किसी और subject पर बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि आज बात होनी चाहिए, तो इसी subject पर बात होनी चाहिए, कम से कम तुम्हें तो इसी subject पर बात करनी चाहिए मुसलमानों पर दोहरी मार पड़ रही है, इन हादसात के चलते दोहरी मार उन पर पड़ रही है–एक मार वह जो मुल्क के सब लोग झेल रहे हैं, उसे यह डर होता है कि कल को वह कचहरी में होगा या मस्जिद में नमाज पढ़ रहा होगा या बाज़ार में जा रहा होगा, वहां बम-ब्लास्ट होगा, तो वह भी मारा जाएगा, ट्रेन में बम-ब्लास्ट होगा, तो वह भी मारा जाएगा। एक मार वह है, जो सारा हिन्दुस्तान झेल रहा है, उसमें मज़हब और जात-पात की बात नहीं है, यह terrorism की वजह से हो रहा है। मुसलमान एक दूसरी मार और झेल रहा है, वह यह कि उसके मज़हब पर, उसकी दाढ़ी पर, उसकी टोपी पर, उसकी पगड़ी पर सवाल उठता है। मैं एयरपोर्ट पर जा रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से कह रहा था कि देखो, बिन-लादेन जा रहा है, किस वजह से–मेरी पगड़ी की वजह से। एक मुश्किल खड़ी हो गई है। मुसलमान दो तरफ से मुसीबत में घिर गया है ...(**व्यवधान**)... अब मैं इसको यहीं रोककर, दूसरी बात पर आता हूं और उस ओर हाऊस की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। हमारी गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आया है, उसमें सेंट्रल एजेंसीज़ की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कही गई है और स्टेट गवर्नमेंट तथा पब्लिक की बात कही गई है कि सब लोग मिल-जुलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं इस गवर्नमेंट से और पहले के गवर्नमेंट वालों से भी सवाल करना चाहता हूं कि यहां बैठे हुए सब लोगों की एक collective responsibility है। सवाल यह खड़ा होता है कि हमने पब्लिक को जोड़ने के लिए क्या किया है? आज हमारे बुजुर्ग दोस्त भी शरद जोशी जी यहां बैठे हैं, अभी कह रहे थे कि सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं हैं, मगर आज जितने टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं वे सब मुसलमान हैं। मैं इसको मान लेता हूं कि यह बात ठीक है। सवाल यह पैदा होता है कि इस मुल्क में मुसलमानों की तादात कितनी है? कम से कम बारह करोड़ तो है ही, ग्यारह करोड़, दस करोड़ मुसलमान हैं। दस करोड़ लोगों को अगर टेररिस्ट मान लिया जाए, अगर हो जाएं या दस करोड़ में दो सौ लोग टेररिस्ट हो जाएं तो क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि बाकी लोगों को टेररिस्ट होने से रोकें, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? मैंने पिछली मर्तबा जब टेररिज्म की बात चल रही थी, एक मर्तबा छोटी सी बहस हुई थी, मैं टाईम नहीं लिया करता हूं, माफ कीजिएगा, मैं महसूस कर रहा हूं कि आप मुझे कहेंगे और मैं उससे बहुत बचता हूं कि कोई मुझे यह कहे कि तुम्हारा टाईम पूरा हो गया है और तुम यहां से जाओ।

**श्री उपसभापति:** मैं बोलने ही वाला था।

**श्री महमूद ए० मदनी:** उपसभापति महोदय, मैं इस हाउस में दो साल में तीसरी मर्तबा बोल रहा हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, पिछली मर्तबा मैंने कहा था कि टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक शॉर्ट टर्म पालिसी होती है और दूसरी लांग टर्म पालिसी होती है। शॉर्ट टर्म पालिसी पर सब लोग बात कर रहे हैं, हमारे जेठमलानी जी ने लांग टर्म पालिसी पर थोड़ी सी बात की है कि कम्युनिटीज़ के साथ बैठना चाहिए, बात होनी चाहिए, कम्युनिटी में वे लोग जो टेररिज्म की मुखालफत कर सकते हैं, मुखालफत कर रहे हैं, मुखालिफ हैं, उनको बैठाना चाहिए, उनको कहना चाहिए, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम आगे बढ़ो और इसके लिए लोगों के बीच पहुंच पर प्रीच करो, लोगों को समझाओ कि यह टेररिज्म जो लोग मुल्क में नौजवानों को दुश्मनी का सबक सिखा रहे हैं, चाहे वे किसी इलाके के हों, चाहे वे असम के नौजवान हों, आज सुबह से इतनी सीरियस बात हो रही है लेकिन हमने यूपी तक संपन्न कर दिया, हमने असम के बारे में बात क्यों नहीं की, तो चाहे असम हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे यूपी हो, नौजवानों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और उनको समझाने के लिए कम्युनिटी को, कम्युनिटी के लीडर्स को, चाहे वह लोकल दर्जे के लीडर हों, उन्हें आगे लाना पड़ेगा, तभी हम लांग टर्म इसका मुकाबला कर सकेंगे। मैं इसको और लंबा नहीं करता, चूंकि इसमें और भी कुछ करने जैसी बात है जिसको कहा जा सकता है। एक तीसरी और आखिरी बात मैं बहुत ही अफसोस और शर्म के साथ अर्ज करूंगा, माफ कीजिएगा, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, यहां हमारे सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आतंकवाद हिन्दुस्तान और दुनिया के लिए एक challenge बन गया है और बना दिया गया है, उसके ऊपर बात हो रही है और लोग party-politics को पहले अहमियत देते हैं और एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, यह टेररिज्म से भी ज्यादा खतरनाक चीज है, इससे हमें ऊपर उठना होगा और एक-दूसरे को मुल्क को सामने रखकर इकट्ठे होकर, एक साथ इसका मुकाबला करना होगा। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि चेयरमैन साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया और बीच में टोका नहीं, शुक्रिया।

†[شری محمود اے۔ مدنی ''اتر پردیش'': آپ سبھاپتی جی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں۔ سب لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے اور کرنی چاہئے، تو میں بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جو حادثات ہوئے ہیں، صرف ابھی کے نہیں شروع سے جو ہوتے چلے آ رہے ہیں، یہ ملک کے لئے نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہیں ملک کے لئے۔ مجھے اس موقع پر ایک شعر یاد آ رہا ہے۔

کسی کے درد اور غم کو، کسی کا ناز کیا جانے

گزرتی صید پر کیا ہے، صیاد کیا جانے

شکار پر کیا گزر رہی ہے یہ شکاری کو کیا خبر؟ میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ جس دن یہ بنارس کا حادثہ ہوا ان تینوں جگہوں کا، شام کو ساڑھے سات بجے کی فلائٹ سے میں بنارس پہنچا۔ جب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ اتر پردیش کی مکھیہ منتری تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچی ہیں، وہاں ایک کانفرنس تھی، ہم لوگ وہاں پہنچے، کانفرنس بالکل educative conference تھی، جس کا پالیٹکس سے، relegion سے ریجنل پالیٹکس سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن کانفرنس آرگنائزرس اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ آج جو انسی ڈینٹ ہوا ہے، اس کی مذمت ہونی چاہئے اور اسی پر بات ہونی چاہئے میں وہ میٹالٹی بتانا چاہتا ہوں کیوں کہ وہاں مسلمان جمع تھے، تو ان کو یہ فکر تھی کہ آج کسی اور سبجیکٹ پر بات نہیں ہونی چاہئے، بلکہ آج بات ہونی چاہئے تو اسی سبجیکٹ پر ہونی چاہئے، کم سے کم تمہیں تو اسی سبجیکٹ پر بات کرنی چاہئے۔ مسلمانوں پر دوہری مار پڑ رہی ہے، ان حادثات کے چلتے دوہری مار ان پر پڑ رہی ہے۔ ایک مار وہ جو ملک کے سب لوگ جھیل رہے ہیں، اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کل کو وہ کچہری میں ہوگا یا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوگا یا بازار میں جا رہا ہوگا، وہاں بم بلاسٹ ہوگا۔ تو وہ بھی مارا جائے گا، ٹرین میں بم بلاسٹ ہوگا تو وہ بھی مارا جائے گا۔ ایک مار وہ ہے، جو سارا ہندوستان جھیل رہا ہے، اس میں مذہب اور ذات پات کی بات نہیں ہے، یہ ٹیرورزم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مسلمان ایک دوسری مار اور جھیل رہا ہے، وہ یہ کہ اس کے مذہب پر، اس کی داڑھی پر، اس کی ٹوپی پر، اس کی پگڑی پر سوال اٹھتا ہے۔ میں ایئرپورٹ جا رہا

†[Transliteration in Urdu Script.]

تھا، تو ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو بن لادن جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ میری پگڑی کی وجہ سے۔ ایک مشکل کھڑی ہوگئی ہے۔ مسلمان دو طرف سے مصیبت میں گھر گیا ہے..."مداخلت"..... اب میں اس کو یہیں روک کر دوسری بات پر آتا ہوں اور اس طرف ہاؤس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارا گورنمنٹ کا جو اسٹیٹ منٹ آیا ہے، اس میں سینٹرل ایجنسیز کی، سینٹرل گورنمنٹ کی بات کہی گئی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ اور پبلک کی بات کہی گئی ہے کہ سب لوگ مل جل کر اس لڑائی کو لڑیں گے۔ میں اس گورنمنٹ سے اور پہلے کے گورنمنٹ والوں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کی ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے۔ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم نے پبلک کو جوڑنے کے لئے کیا، کیا ہے؟ آج ہمارے بزرگ دوست شری شرد جوشی جی یہاں بیٹھے ہیں، ابھی کہہ رہے تھے کہ سارے مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں، مگر آج جتنے ٹیررسٹ پکڑے جا رہے ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ میں اس کو مان لیتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ کم سے کم بارہ کروڑ تو ہیں ہی، گیارہ کروڑ، دس کروڑ مسلمان ہیں۔ دس کروڑ لوگوں کو اگر ٹیررسٹ مان لیا جائے، اگر ہو جائیں یا دس کروڑ میں دو سو لوگ ٹیررسٹ ہو جائیں تو کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ باقی لوگوں کو ٹیررسٹ ہونے سے روکیں، اس کے لئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پچھلی مرتبہ جب ٹیررزم کی بات چل رہی تھی، ایک مرتبہ چھوٹی سی بحث ہوئی تھی، میں ٹائم نہیں لیا کرتا ہوں، معاف کیجئے گا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھے کہیں گے اور میں اس سے بہت بچتا ہوں کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ تمہارا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور تم یہاں سے جاؤ۔

**شری اُپ سبھاپتی:** میں بولنے ہی والا تھا۔

**شری محمود اے. مدنی:** اُپ سبھاپتی مہودے، میں اس ہاؤس میں دو سال میں تیسری مرتبہ بول رہا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک شارٹ ٹرم پالیسی ہوتی ہے اور دوسری لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے۔ شارٹ ٹرم پالیسی پر سب لوگ بات کر رہے ہیں، ہمارے جیٹھ ملانی جی نے لانگ ٹرم پالیسی پر تھوڑی سی بات کی ہے کہ کمیونٹیز کے ساتھ بیٹھنا چاہئے، بات

ہونی چاہیئے، کمیونٹی میں وہ لوگ جو ٹیررزم کی مخالفت کر سکتے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، مخالف ہیں، ان کو بیٹھانا چاہیئے، ان کو کہنا چاہیئے، ان کے اوپر ذمہ داری ڈالنی چاہیئے کہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، تم آگے بڑھو اور اس کے لئے لوگوں کے بیچ پہنچ کر پریچ کرو، لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ ٹیررزم جو لوگ ملک میں نوجوانوں کو دشمنی کا سبق سکھا رہے ہیں، چاہے وہ کسی علاقے کے ہوں، چاہے وہ آسام کے نوجوان ہوں، آج صبح سے اتنی سیریس بات ہو رہی ہے لیکن ہم نے یو پی تک تمپنن کر دیا، ہم نے آسام کے بارے میں بات کیوں نہیں کی، تو چاہے آسام ہو، چاہے ناگالینڈ ہو، چاہے یو پی ہو، نوجوانوں کو سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑیگا

اور ان کو سمجھانے کے لئے کمیونٹی کو، کمیونٹی کے لیڈرس کو، چاہے وہ لوکل درجے کے لیڈر ہوں، انہیں آگے لانا پڑے گا، تبھی ہم لانگ ٹرم اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ میں اس کو اور لمبا نہیں کرتا، چونکہ اس میں اور بھی کچھ کرنے جیسی بات ہے جس کو کہا جا سکتا ہے۔ ایک تیسری اور آخری بات میں بہت ہی افسوس اور شرم کے ساتھ عرض کرونگا، معاف کیجئے گا، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹی منہ بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ یہاں ہمارے سب بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آتنک واد ہندستان اور دنیا کے لئے ایک چیلنج بن گیا ہے اور

بنا دیا گیا ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور لوگ پارٹی پالیٹکس کو پہلے اہمیت دیتے ہیں، اور ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، یہ ٹیررزم سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، اس سے ہمیں اوپر اٹھنا ہوگا اور ایک دوسرے کو ملک کو سامنے رکھ کر اکٹھے ہو کر، ایک ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرونگا کہ چیئرمین صاحب نے مجھے بولنے کا موقعہ دیا اور بیچ میں ٹوکا نہیں، شکریہ۔

[''ختم شد'']

---

†[Transliteration in Urdu Script.]

**श्री अमर सिंह:** उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि हम लोगों ने असम की बात नहीं उठाई है जब कि असम की बात हम लोगों ने उठाई है और माननीय गृहमंत्री जी से कहा कि वह असम के बारे में बताएं....(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** नहीं, नहीं, असम के बारे मे बात उठाई गई है और आज शाम को असम के बारे में स्टेटमेंट भी होगा।

A separate statement will be made by the Home Minister on the situation in Assam.

**श्री कलराज मिश्र** (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, वाराणसी, लखनऊ और फैजाबाद में हुए बम विस्फोट के कारण जो जन हानि हुई हैं, जो लोग जख्मी हुए हैं, उस पर आज चर्चा चल रही है। यह बात सही है कि जो बाकी के वक्ताओं ने आतंकवाद के बारे में अपनी बात रखी, अपने-अपने तर्क रखे। मैं समझता हूं कि आतंकवाद के बारे में जिस तरीके से ये घटनाएं घटित हो रहीं हैं, ये केवल 23 नवंबर को घटित नहीं हुई। वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर--ये धार्मिक केंद्र हैं और इन केंद्रों को ध्वस्त करने के लिए इसके पूर्व भी कई बार आतंकवादी घटनाएं घटित हुईं। उस समय भी चर्चा हुई थी और उस समय चर्चा के दौरान बातें कहीं गई थीं। जैसे आज का वक्तव्य है, इस वक्तव्य के अंदर सातवां और आठवां पैरा है, इसमें साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि सबको सामूहिक रूप से मिलकर, संकल्प शक्ति के आधार पर आतंकवाद का जबरदस्त विरोध करना चाहिए, अभियान चलाना चाहिए। यह बात हमेशा कही गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से प्रयत्न होने चाहिए थे, नहीं हो पाए। जिम्मेदारी इसमें किसकी ज्यादा बनती है, प्रश्न इस बात का है। हम वाराणसी गए। वाराणसी जाने के बाद, जिस तरीके से घटनास्थल को देखा, वाराणसी कचहरी में दो जगह बम विस्फोट हुए और जब विस्फोट हुए, तो उस समय प्रथम दृष्टया तो यही लगा कि वहां श्रीमान् अजय राय जी, जो पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं, वे आज कोर्ट में आए हुए हैं, इनको मारने के लिए ये घटनाएं घटित हुईं। तात्कालिक प्रतिक्रिया यही थी, लेकिन जब पता लगा कि नहीं, लखनऊ में भी यह हुआ है, फैज़ाबाद में भी हुआ है, तब लगा कि ये तो सिलसिलाबद्ध आतंकवादी घटनाएं हैं। उनकी सुरक्षा कम हो गई थी, इसके बारे में आदरणीय डा॰ जोशी जी ने कहा कि उस पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे विनय जी हैं, इनके ऊपर भी अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जा चुके हैं, इनकी भी सुरक्षा जो दिल्ली से प्राप्त होती थी, वह हटा ली गई। मैं समझता हूं, इस पर भी आपको प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। ये घटनाएं हुई क्यों? इन घटनाओं का जो स्वरूप है, श्रीमान अमर सिंह जी ने उसका वर्णन किया है कि बम साइकिल पर था और अमोनियम नाइट्रेट डालकर उसका उपयोग किया गया था, तो किस आतंकवादी संगठन की तरफ से यह घटना की गई है? पूर्व में जैसे आतंकवादी संगठनों ने इस तरह की घटना अयोध्या में की थी, संकटमोचन में की थी, गोरखपुर में की थी,उसी प्रकार का स्वरूप यहां भी रहा है और ये जो आतंकवादी संगठन हैं, ये आतंकवादी संगठन सुनियोजित तौर पर हमले कर रहे हैं, और इनकी तरफ से सुनिश्चित तौर पर दो बिन्दु निर्धारित किए गए हैं और उनका लक्ष्य यह है कि इनके सांस्कृतिक केंद्र को ध्वस्त किया जाए, इनके आर्थिक केंद्र को ध्वस्त किया जाए और इनके सैनिक केंद्र को ध्वस्त किया जाए। इसके पहले जब चर्चा चली थी, आंतरिक सुरक्षा के क्रम में, तब मैंने उस चर्चा के दौरान यह कहा था कि पी॰ओ॰के॰ के अंदर आई॰एस॰आई॰ के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी। उसमें सभी आतंकवादी संगठन उपस्थित थे ओर आई॰एस॰आई॰. के वहां डायरेक्टर थे और उन्होंने बाकायदा यह तय किया था-अयोध्या, वाराणसी, देहरादून, बंगलौर-इनको टार्गेट बनाया था। यह खबर रॉ ने दी थी, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हुई। लगातार ये घटनाएं चल रही हैं और केवल इतना ही नहीं है, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आतंकवादी घटनाएं, जब मैंने कहा कि इनका लक्ष्य निर्धारित है, सुनियोजित है, तो केवल आतंकवाद के रूप में उसको मत देखिए। इसको छद्म युद्ध के रूप में भी देखिए। इसको प्रॉक्सी नार के रूप में भी देखिए और प्रॉक्सी वार है, तो उसके अनुरूप योजना आपको बनानी पड़ेगी और यह कह कर नहीं चलना पडेगा कि सब लोग मिलकर करें और सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सुनियोजित तौर पर परस्पर सामंजस्य के आधार पर, जिस तरीके से रणनीति बनाकर इस युद्ध के विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए, यह अभियान नहीं चलाया जा रहा है और एक-दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। केंद्र सरकार कहे कि राज्य सरकार को हमने सूचना दे दी थी, राज्य सरकार कहे कि केंद्र सरकार ने हमें सूचना नहीं दी, यह सामंजस्य की कमी है। इस सामंजस्य की कमी के कारण इस प्रकार की घटनाओं का, इस प्रकार के युद्ध का हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं और जब यह युद्ध है, तो हमारी एकता और अखंडता को खतरा है। वाराणसी न्यायालय पर हमला करना, यह केवल मात्र इतना ही नहीं है, लखनऊ में हमला करना, केवल मात्र इतना नहीं है, अयोध्या में हमला करना, केवल मात्र इतना ही नहीं है, लोगों को आतंकित करने की कोशिश की जा रही है। महोदय, जहां मैं इस आतंकवादी घटना की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, वहीं मैं वाराणसी के नागरिकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन

**3-00 P.M.**

करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि इतनी भयंकर घटना होने के बावजूद भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, उसी दिन देव-दीपावली भी थी–देव-दीपावली इतने शानदार तरीके से उन्होंने मनाई कि लगा कि हमारे सामने कोई घटना नहीं हुई। वाराणसी के नागरिक, चाहे हिन्दू हों या मुसलमान हों, सब सामूहिक रूप से परस्पर सद्भाव के साथ चले। इस प्रकार नागरिक तो आपके साथ हैं, साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन और शासन को सुनियोजित तौर पर इस प्रॉक्सी वार का मुकाबला करना पड़ेगा। प्रॉक्सी वार के मुकाबले के लिए आपको गुप्तचरीय व्यवस्था भी ठीक करना पड़ेगी, आपको आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित होना पड़ेगा। गुप्तचरीय व्यवस्था को ठीक करने के लिए आधुनिकतम सैन्य उपकरण देने पड़ेंगे ताकि वे उनका मुकाबला कर सकें और उन्हें यह शिकायत करने की आवश्यकता न पड़े। हमें इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी। यद्यपि यह बात आयी, श्रीमान् सतीश मिश्र जी ने भी कहा और अमर सिंह जी ने भी कहा, शरद जी ने उस पर ज्यादा ध्यान आकर्षित किया कि हम सीआईडी में उसको भेजते हैं, जिसको नाकाबिल समझते हैं। जब सीआईडी विभाग में जाता है तो वह समझता है कि हमें दंड दिया गया है, पनिशमेंट पोस्टिंग है। आप उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसको आप इस प्रकार से व्यवस्थित करिए, जिसके आधार पर वह ठीक से काम कर सके, समोसा में जा न सके। अभी कहा कि समोसा खिलाकर इधर-उधर किया जा सकता है। यह गुप्तचरीय व्यवस्था हमें इस प्रकार से दुरुस्त करनी पड़ेगी। अभी विनय कटियार जी ने एक बात और रखी कि यहां सूचना तो दे दी जाती है, रिपोर्ट तो भेज दी जाती है लेकिन जो संबंधित विभाग का मंत्री या मंत्रालय है, वह उसको पढ़ नहीं पाता। पढ़ नहीं सकने के कारण उसके अनुरूप व्यवस्था नहीं हो पाती। यह बात सही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, कोई जात नही है, कोई बिरादरी नहीं है, कोई हिन्दू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। आतंकवादी तो आतंकवादी ही होता है। श्रीमान, शरद जी यह कह रह थे कि यह बात तो सही है कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं लेकिन जो भी पकड़े जाते हैं, वे मुस्लिम हैं–यह दुर्भाग्यजनक है। यह बात सही है कि मुसलमान और हिन्दू, दोनों ने मिलकर 1857 की क्रांति में जबर्दस्त भाग लिया था और 1857 की क्रांति के अंदर हिन्दू और मुसलमानों में जो एकता स्थापित हुई थी, उसी एकता को स्थापित करने की आज जरूरत है। इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न होने चाहिए। एक दूसरे को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अगर सामूहिक रूप से प्रयत्न होंगे तो जो भी मुसलमान आतंकवादी के रूप में उभरकर आते हैं, उनको भी अपने साथ जोड़कर देश की मुख्य धारा के साथ हम जोड़ें। लेकिन आतंकवादियों के विरुद्ध एक अभियान चलाना पड़ेगा और उस अभियान को चलाने में सरकार विफल हुई है। इसलिए मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी विशेष है। स्टेट गवर्नमेंट की उतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र माननीय राम जेठमलानी जी ने किया। यह एक केन्द्र का विषय है। जब यह केन्द्र का विषय है तो केन्द्र उसके लिए क्या कर रहा है? गृह मंत्री जी ने कहा कि गुप्तचरीय विभाग इस मामले में विफल हो गया लेकिन केवल विफल हो गया यह कहने से काम नहीं चलेगा। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि अगर तीन आतंकवादी पकड़े जाते हैं? कोर्ट से भाग जाते हैं, तो फिर यह हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के लचरपन को प्रकट करता है यह भी दुखद है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं–अभी ई-मेल से खबर दी जा रही है कि फिर से हमला करने वाले हैं, पूर्व सूचना देकर हमला कर रह हैं। सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि वे पूर्व सूचना दे रहे हैं कि हम तुम्हारे यहां हमला करने वाले हैं, हम विस्फोट करने वाले हैं, पूर्व सूचना मिलने के बावजूद भी जैसी चुस्त व्यवस्था करनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है। मान्यवर उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो टारगेट बनाया, सांस्कृतिक केन्द्र को टारगेट बनाया है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों को टारगेट बनाया है। केवल मंदिर को टारगेट बनाया, ऐसा नहीं है, उन्होने मस्जिद को भी टारगेट बनाया है। उन्होंने दोनों को टारगेट बनाया है, अब वे न्यायालय को टारगेट बना रहे हैं। वे भारत के लोकतंत्र को ध्वस्त करना चाहते हैं, न्यायालय लोकतंत्र का एक मज़बूत स्तम्भ है, उसको ध्वस्त करना चाहते हैं। इसके लिए सामूहिक रूप से सबको विचार करना पड़ेगा। पार्टी की दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा और जब हम दलगत राजनीति से ऊपर उठते हैं तो पोटा के बारे में आलोचना होती है, ठीक है, उसमें कुछ खामी आपको लगती है तो एक अच्छा कानून बनाइए ऐसा कानून बनाइए जो आतंकवादियों को दंडित कर सके।

**श्री उपसभापति:** समाप्त करें।

**श्री कलराज मिश्र:** सर, मैं दो मिनट और लूंगा। उसके अनुरूप कानून बनाना चाहिए। यह कह कर उस पर टोकना नहीं चाहिए कि यह नहीं, यह नहीं। आप ले आईए कानून, लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग करने के नाम पर कानून ही नहीं बने तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। मगर इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और दुरुपयोग न हो

उसके लिए व्यवस्था करिए। इसलिए मान्यवर, फिर से पोटा की जरूरत है। यू०पी० कोका की बात कही गई। ठीक है अगर आतंकवाद के विरुद्ध यू०पी० कोका है, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग हुआ तो वह खतरनाक है। तो इसका दुरुपयोग नहीं होने पाए, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। तो उसके अनुरूप कानून बनाने की आवश्यकता है और कानून बनाने के साथ अगर व्यक्ति दंडित होगा, तो दंडित होने वाले आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी को मारने के लिए कोयम्बटूर का ब्लास्ट हुआ होगा और अगर उसके सूत्रधार केरल की जेल में बंद हुए होंगे तो उनको प्रोत्साहन नही देना चाहिए। अगर अफजल गुरू को दंडित करने की बात की गई तो उसका क्या राजनीतिक फायदा होता है, क्या राजनीतिक फायदा नहीं होता है, इसको किनारे रखना चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए। अगर दंडित नहीं किया गया है तो हमने आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। स्टेटमेंट का सातवां और आठवां जो पैरा दिया है.....(**व्यवधान**)....

**श्री उपसभापति:** कलराज जी, समाप्त कीजिए?

**श्री कलराज मिश्र:** इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटे और अपनी जिम्मेदारी का समुचित रूप से निर्वहन करे और केन्द्र का विषय मानकर प्रोक्सी वार के रूप में इसको लेते हुए उसके अनुरूप अभियान चलाए ताकि युद्ध में आतंकवादी प्रोक्सी वार के रूप में वे जो काम करना चाहते हैं वह सफल न होने पाए, इस प्रकार उसमें हम विजय प्राप्त करेंगे, अगर इस मानसिकता से प्रेरित होकर काम करेंगे तो न संकटमोचन की घटना होगी, न न्यायालयों पर घटना होगी। आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MANOHAR JOSHI (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman Sir, a very important discussion is taking place in this House. I am, indeed, thankful to you for giving me an opportunity to speak.

Sir, what happened in Uttar Pradesh is known to everybody and everybody is worried about the terrorist activities taking place in our country. I have gone through the statement made by the hon. Minister very carefully, and I felt that such statements have been made in the House a number of times; there is nothing new about it. If we go through the earlier statements made by hon. Ministers, we would find that the same kind of statements are being repeated in the House again and again.

**श्री अमर सिंह:** सर, माननीय मंत्री सुब्बारामी रेड्डी जी सो रहे हैं, उनको जगा दीजिए।

**श्री उपसभापति:** नहीं, अब तो हंस रहे हैं। जब मैंने देखा तो हंस रहे हैं।

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, his contention is that the Ministers have been sleeping and, therefore, such activities are taking place.

**प्रो० राम देव भंडारी (बिहार):** सर, वे साधक हैं, साधना कर रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Ministers are thinking!

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, the incidents took place in Uttar Pradesh but this has repercussions all over the country because it is not the first time that such incidents have taken place. As for me, I have seen it right from 1992 when such attacks took place in the city of Mumbai. Thereafter, the activities continued for a pretty long time. Terrorist activities are increasing in all parts of our country. We keep discussing it in the House without any results. Speeches are made and Government always gives assurances, as it has done in the last paragraph. They have said, "We will not allow these anti-national forces to disturb peace and communal harmony in the country." It means, the Government is aware about the seriousness of these incidents. The question before all of us is, whether proper actions are being taken, whether the Government is very serious and whether the Government really

wants to stop these activities. During this discussion, the emphasis should be that in future no such bomb blasts take place in our country. The question is, whether by debate or discussion these things can be achieved. Nobody is sure about his life in country. The Constitution of India itself guarantees the right to live. But, is this right to live given by this Government to us today? If you ask me, Sir, I would say that the whole country is in danger today. Nobody knows what will happen in any part of the country at any time. The lives of Indians have become very serious and this is only because we are not prepared to accept the facts as they are. We talk of national integration; we talk of unity of the country, but, at the same time, we are not prepared to take strict measures to stop the terrorism and to stop the activities which take place everywhere in the country. Sir, therefore, my first suggestion would be, the strict enforcement of laws is absolutely necesary and all of us unanimously decide that wherever necessary we will take the action and those who are arrested for terrorism we would never stand by them. Sir, the incident is known to everybody that in the House there was a discussion also about Afzal Guru. We have demanded in this House that Afzal Guru should be hanged forthwith. How many months have passed? I am sure, if Afzal Guru is punished, terrorists would not dare to do what they did again in Uttar Pradesh. But is this House prepared to pass a unanimous resolution that Afzal Guru should be hanged fortwith? We are not prepared to do it for political interests. I would only say that we always divide on such issues because we give more importance to politics than discouraging terrorism in the country. Sir, I do not understand why we are afraid of everything. If there is a terror of terrorists, then there should be terror about the Government also. Those who do such types of anti-national activities must get scared as to what would happen if they are arrested.

Sir, according to me, it is not impossible to stop terrorism, provided the Government seriously wants to do it. But, this is very unfortunate that the Government is not prepared to take steps. The enforcement of law is not being done in the country and, therefore, the state-sponsored terrorism has also not stopped. The question is raised whether all Muslims are terrorists. I would say that we have never said that all Muslims are terrorists, but, at the same time, the Government has also accepted in the House that state-sponsored terrorism is there, and if State-sponsored terrorism is there, we all know that this is...(*Interruptions*)... I am referring to Pakistan, the cross-border terrorism ..(*Interruptions*)... Terrorists have gone to such an extent that the Parliament House was also attacked. I remember, when the Parliament House was attacked, my Party had made a demand that if the Government did not want terrorism in this country, our country must be brave enough to attack Pakistan. But, we did not do it because we were always involved in politics. According to me, only two things are enough to stop all these things. Number one, our country must attack Pakistan so that the terrorists will get scared...(*Interruptions*)...

SHRI AMAR SINGH: This is very wrong...(*Interruptions*)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: This is highly objectionable...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Where are we going?...(*Interruptions*)...

**श्री विनय कटियार:** ये बोल रहे हैं, तो इनको क्यों दिक्कत हो रही है। ...(**व्यवधान**)... ये अपनी बात कह रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप भी सरकार में थे। ...(**व्यवधान**)...

**श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा):** इनसे पूछिए कि पाकिस्तान की क्या हालत है? ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** आज़मी साहब, आप छोड़िए...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए... (**व्यवधान**)..

SHRI S.S. AHLUWALIA: Hundreds of reports point out that Pakistan is the breeding centre of terrorism...(*Interruptions*)...

**श्री उपसभापति:** आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... मिस्टर शाहिद साहब, आप बैठिए। इसमें क्या है? ...(**व्यवधान**)... बैठिए। Please conclude.

SHRI EKANATH K. THAKUR (Maharashtra): We are saying that we should attack the terrorist camps...(*Interruptions*)...

**श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** मनोहर जोशी जी ने कुछ गलत नहीं बोला है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** सैकड़ों रिपोर्ट्स हैं। वहां पर कहा है कि Pakistan is the breeding centre of terrorism. What is wrong in attacking their camps? ...(*Interruptions*)...

SHRI AMAR SINGH: Attacking terrorist camps is different....(*Interruptions*)...

**श्री उपसभापति:** यह क्या बात है?..(**व्यवधान**).. आप बैठिए। ..(**व्यवधान**)..आप बैठिए। ..(**व्यवधान**)..आप बैठिए, आप बैठिए।..(**व्यवधान**).. आप बोलिए, प्लीज कन्कलूड कीजिए।..(**व्यवधान**)..आप बैठिए। Mr. Manohar Joshi is enough to defend himself...(*Interruptions*)...

SHRI MANOHAR JOSHI: My first point is that if terrorists are coming from Pakistan and if these terrorists, in one way or other, are supported by Pakistan, and if we do not want further...(Interruptions)...

**श्री उपसभापति:** पाणि जी, Allow him to speak...(*Interruptions*)... आप बात करते रहेंगे, यह क्या बात है? ...(**व्यवधान**)... देखिए, हर मैम्बर को हाउस में डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। मैं किसी से नाराज नहीं हूं और आप से इलतिजा कर रहा हूं कि आप डेकोरम मेंटेन कीजिए।

SHRI MANOHAR JOSHI: If you really want to tackle terrorism, we have to take strict steps in the country. This is very unfortunate that number of people are of the opinion that this is the best way to stop cross-border terrorism, but they do not want to take any action against Pakistan. I would like to ask such people as to why they think so and how they will be able to save the lives of the people of our country ...(*Interruptions*)... I will finish within one or two minutes.

Secondly, as I have already said, in our country, we are unnecessarily following the method of humanity for people towards are culprits.

Sir, as regards Afzal Guru, if you hang him, I am sure, other terrorists will also be scared, and they would never be able to do such acts... (*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already made that point very clear.

SHRI MANOHAR JOSHI: Therefore, I would say that such type of statements would not be enough to save the lives of the people, if the Government really wants to save them. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All the major parties have exhausted the time allotted. Now, I will give two minutes each to the remaining Members so that we can conclude.

(*Interruptions*) देखिए, यह strength के ऊपर है। उनके तीन आदमी बोले हैं, जबकि उनके 50 आदमी हैं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री शाहिद सिद्दिकी:** सर मैंने नोटिस दिया था। मुझे अभी तक मौका नहीं मिला।

†**شری شاہد صدیقی :** سر، میں نے نوٹس دیا تھا۔ مجھے ابھی تک موقع نہیں ملا۔

**श्री उपसभापति:** मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि this is not the only business. There is other business also. (*Interruptions*) मैं opportunity दे रहा हूं। I am calling you. मैं आपको भी बुलाऊं ..(**व्यवधान**)...

**श्रीमती वृंदा कारत:** सर, आप हमारे ऑनरेबल सिद्दिकी साहब को मौका दीजिए।

**श्री उपसभापति:** मैं मौका दूँगा। Should I not say 'stick to the time-limit'? I have to regulate. (*Interruptions*) Shri Abu Asim Azmi. You have made a special request for two minutes.

**श्री अबू आसिम आज़मी:** शुक्रिया सर, आपने मुझे वक्त दिया। मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं मुल्क में जहां-जहां दहशतगर्दी हमले हो रहे हैं, मैं उसकी दिल की गहराइयों से मजम्मत करता हूं और जो लखनऊ में, फैजाबाद में और वाराणसी में हुआ है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और डिमांड करता हूं कि जल्द-से-जल्द सही कसूरवार को पकड़ा जाए और उसे फाँसी के फंदे पर लटका दिया जाए लेकिन मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूं कि क्या गाँधी जी को मारने वाले को वकील करने का हक नहीं था? क्या राजीव गाँधी और इन्दिरा गाँधी को कत्ल करने वाले को वकील करने का हक नहीं था? मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आतंकवादी है, तो उसे सजा दीजिए, लेकिन उसे ज़रा प्रूव करने का वक्त तो दीजिए। सर, मैं पकड़ा गया था, तो राम जेठमलानी साहब, वे यहां से चले गए, वे मेरे वकील थे? तो बाला साहब ठाकरे ने उनको कहा था कि अबू आसिम एक टेरोरिस्ट है, उसका मुकदमा मत लीजिए। उन्होंने उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी कि आप मेरे पर्सनल मामले में दखल नहीं दे सकते, मैं जानता हूं कि कौन क्या है। मुकदमा चलने दीजिए, साफ जाहिर हो जाएगा। इसलिए मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जो लोग पकड़े गए हैं, क्या उन्हें वकील करने का हक है या नहीं? अगर वकील लोग किसी को कोर्ट के अन्दर इस तरह मारेंगे, तो मुझे लगता है कि इंसाफ खत्म हो जाएगा। हां, अगर कसूरवार है, तो उनको फांसी दीजिए, लेकिन कसूरवार तय कौन करेगा? ...(**व्यवधान**)... सर, अभी मेरी बात बाकी रह गई है।

सर, यहां पर कुछ संगठन ऐसे हैं, जो खुलेआम हथियारों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी नज़र उधर नहीं जा सकती? मैं कह रहा हूं कि आप सबको चेक कीजिए। अभी ये बात कर रहे हैं, इधर वाले ये बात कर रहे हैं, उधर वाले उस पर बात कर रहे हैं। मैं पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल ऊपर उठकर बात कर रहा हूं। मेरे दिल की तमन्ना है कि किसी तरह से इस देश के अन्दर से आतंकवाद खत्म हो। सर, आतंकवाद कैसे खत्म होगा? सर, जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। सर, आप आज देख लीजिए। मालेगांव के अन्दर ब्लास्ट हुआ, तो उनको सिर्फ एक लाख दिया गया और हैदराबाद में हुआ, मुम्बई में हुआ, तो उनको 6 लाख दिया गया। होम मिनिस्टर साहब बताएं कि पैमाना क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? सर, इस तरह से क्यों किया जा रहा है? सर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर किसी आदमी को पकड़ लिया जाए और पुलिस कहे कि वह आतंकवादी है और उसका मुकदमा न चले, तो वह आतंकवादी हो गया। सर, मैंने मुम्बई के अन्दर देखा है कि हम चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं, कि मुम्बई के रेलवे के ब्लास्ट की एन्क्वायरी सीबीआई से करवा दो, ताकि वे लोग जो कह रहे हैं, असत्य है, उनके मुंह पर थप्पड़ लग जाए। आप उनको कह दो कि सीबीआई की एन्क्वायरी में भी यह आ गया कि तुम आतंकवादी हो, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। वह क्यों तैयार नहीं है? क्या सरकार जान-बूझकर किसी को आतंकवादी बनाना चाहती है?...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** आपकी स्पीच में कहीं भी उत्तर प्रदेश नहीं आ रहा है। आप पूरे हिन्दुस्तान में चले गए हैं।

**श्री अबू आसिम आज़मी:** मैं पूछना चाहता हूं कि वे लोग, बेचारे ...(**व्यवधान**)...कम पढ़े-लिखे लोग आतंकवाद के अन्दर जबर्दस्ती पकड़े गए, घाटकोपर के ब्लास्ट के अन्दर, वे सारे लोग पांच-पांच साल अन्दर रहने के बाद बेगुनाह छूट गए। सर, वे आतंकवादी नहीं थे। अगर उनका मुकदमा नहीं चला होता, तो क्या वे छूटते? मैं कहना चाहता हूं कि

†[Transliteration in Urdu Script.]

आप ऐसे लोगों के ऊपर जल्द-से-जल्द, जो पुलिस वाले या जो सरकार जबर्दस्ती किसी को पकड़कर आतंकवादी बनाकर पेश कर रही है, अगर वे बेकसूर छूटते हैं, तो उन पर आप क्यों नहीं ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** आपका क्लैरिफिकेशन हो गया, आप बैठिए। Please conclude.

**श्री अबू आसिम आज़मी:** नहीं, सर, मेरी बात पूरी नहीं हुई। सर, एक चीज़ मेरे दिल में बाकी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है, हम उसके पिछलग्गू बनते जा रहे हैं। जिस तरह फिलिस्तीन के अन्दर ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** देखिए, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। यूपी से आप दुनिया को चले गए...(**व्यवधान**)...

**श्री अबू आसिम आज़मी:** हमारे देश में वे लोग जो आज फिलिस्तीन में मुसलमानों को निहत्थे मार रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not the issue. ...*(Interruptions)*... That is not the issue.देखिए, आप समय चाहते हैं और कहते कुछ हैं, यह ठीक नहीं है। शाहिद सिद्दिकी साहब।

**श्री अबू आसिम आज़मी:** सर, मैं यह नहीं कह रहा हूं। आप मेरा दुख-दर्द समझने की कोशिश कीजिए।

**श्री उपसभापति:** आपका दुख कुछ भी होगा।

**श्री अबू आसिम आज़मी:** मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि कहीं आतंकवाद बढ़ने के पीछे ये चीज़ें भी तो नहीं हैं और जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर उन्हें कोर्ट कचहरी में जाने को भी नहीं मिलेगा ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** आप खत्म कीजिए। ...(**व्यवधान**)... शाहिद सिद्दिकी साहब, आप बोलिए ...(**व्यवधान**)...

**श्री अबू आसिम आज़मी:** अगर उनकी हिफाज़त नहीं होगी तो कहीं ऐसा न हो कि वे आईएसआई या लश्कर-ए-तौएबा के लोगों के कॉन्टैक्ट में आ करके इस माहौल को और बढ़ाएं। सर, मैं इन बातों को जानना चाहता हूं, मुझे होम मिनिस्टर साहब से इन सब बातों का जवाब चाहिए धन्यवाद, शुक्रिया।

†[شری ابو عاصم اعظمی ''اتر پردیش'': شکریہ سر، آپ نے مجھے وقت دیا۔ میں صرف کلیری فکیشن پوچھنا چاہتا ہو۔ سب سے پہلے تو میں ملک میں جہاں جہاں دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں، میں اس کی دل کی گہرائیوں سے مذمت کرتا ہوں اور جو لکھنؤ میں، فیض آباد میں اور وارانسی میں ہوا ہے، میں اس کی پر زور مذمت کرتا ہوں اور ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد صحیح قصوروار کو پکڑا جائے اور اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ لیکن میں کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا گاندھی جی کو مارنے والے کو وکیل کرنے کا حق نہیں تھا؟ کیا راجیو گاندھی اور اندرا گاندھی کو قتل کرنے والے کو وکیل کرنے کا حق نہیں تھا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آتنک وادی ہے تو اسے سزا دیجئے لیکن اسے ذرا پروف کرنے کا وقت تو دیجئے۔ سر، میں پکڑا گیا تھا، تو رام جیٹھ ملانی صاحب، وہ یہاں سے چلے گئے، وہ میرے وکیل تھے، تو بالا صاحب ٹھاکرے نے ان کو کہا تھا کہ ابو عاصم ایک ٹیررسٹ ہے، اس کا مقدمہ مت لیجئے۔ انہوں نے اس وقت ایک چٹھی لکھی تھی کہ آپ میرے پرسنل معاملے میں دخل نہیں دے سکتے، میں جانتا ہوں کہ کون کیا ہے؟

†[Transliteration in Urdu Script.]

مقدمہ چلنے دیجئے، صاف ظاہر ہو جائے گا۔ اس لئے میں ہوم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، کیا انہیں وکیل کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ اگر وکیل لوگ کسی کو کورٹ کے اندر اس طرح ماریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ انصاف ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر قصوروار ہیں تو ان کو پھانسی دیجئے، لیکن قصوروار طے کون کریگا؟ --مداخلت-- سر، ابھی میری بات باقی رہ گئی ہے۔

سر، یہاں کچھ سنگھٹن ایسے ہیں، جو کھلے عام ہتھیاروں کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی نظر ادھر نہیں جا سکتی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو چیک کیجئے۔ ابھی یہ بات کر رہے ہیں، ادھر والے یہ بات کر رہے ہیں، ادھر والے اس پر بات کر رہے ہیں۔ میں پارٹی پالیٹکس سے بالکل اوپر اٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ میرے دل کی تمنا ہے کہ کسی طرح سے اس دیش کے اندر سے آتنک واد ختم ہو۔ سر، آتنک واد کیسے ختم ہوگا؟ سر، ظلم اور ناانصافی کی کوکھ سے آتنک واد پیدا ہوتا ہے۔ سر، آپ آج دیکھ لیجئے۔ مالیگاؤں کے اندر بلاسٹ ہوا، تو ان کو صرف ایک لاکھ دیا گیا اور حیدرآباد میں ہوا، ممبئی میں ہوا، تو ان کو چھ لاکھ دیا گیا۔ ہوم منسٹر صاحب بتائیں کہ پیمانہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سر، اس طرح سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ سر، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو پکڑ لیا جائے اور پولس کہے کہ وہ آتنک وادی ہے اور اس کا مقدمہ نہ چلے، تو وہ آتنک وادی ہو گیا۔ سر، میں نے ممبئی کے اندر دیکھا ہے کہ ہم چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ ممبئی کے ریلوے کے بلاسٹ کی انکوائری سی۔بی۔آئی۔ سے کروا دو، تاکہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، جھوٹ ہے، ان کے منھ پر تھپڑ لگ جائے۔ آپ ان کو کہہ دو کہ سی۔بی۔آئی۔ کی انکوائری میں بھی یہ آ گیا کہ تم آتنک وادی ہو، لیکن سرکار تیار نہیں ہے۔ وہ کیوں تیار نہیں ہے؟ کیا سرکار جان بوجھ کر کسی کو آتنک وادی بنانا چاہتی ہے؟ --مداخلت--

**شری اپ سبھاپتی:** آپ کی اسپیچ میں کہیں بھی اتر پردیش نہیں آ رہا ہے۔ آپ پورے ہندوستان میں چلے گئے ہیں۔

**شری ابوعاصم اعظمی:** میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ، بے چارے --مداخلت-- کم پڑھے لکھے لوگ آتنک واد کے اندر زبردستی پکڑے گئے، گھاٹ کوپر کے بلاسٹ کے اندر، وہ سارے لوگ پانچ پانچ سال اندر رہنے کے بعد بے گناہ چھوٹ گئے۔ سر، وہ آتنک وادی نہیں تھے۔ اگر ان کا مقدمہ نہیں چلا ہوتا، تو کیا وہ چھوٹتے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کے اوپر جلد سے جلد،

جو پولس والے یا جو سرکار زبردستی کسی کو پکڑ کر آتنک وادی بنا کر پیش کر رہی ہے، اگر وہ بے قصور چھوٹتے ہیں، تو ان پر آپ کیوں نہیں۔۔مداخلت۔۔

**شری اپ سبھاپتی:** آپ کا کلیری فکیشن ہو گیا، آپ بیٹھئے۔ Please conclude۔

**شری ابو عاصم اعظمی:** نہیں، سر، میری بات پوری نہیں ہوئی۔ سر، ایک چیز میرے دل میں باقی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا آتنک وادی ہے، ہم اس کے بچھ لگو بنتے جا رہے ہیں۔ جس طرح فلسطین کے اندر۔۔مداخلت۔۔

**شری اپ سبھاپتی:** دیکھئے، آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ یو۔پی۔ سے آپ دنیا میں چلے گئے ہیں۔۔مداخلت۔۔

**شری ابو عاصم اعظمی:** ہمارے دیش میں وہ لوگ، جو آج فلسطین میں مسلمانوں کو نہتھے مار رہے ہیں ۔۔مداخلت۔۔

**شری اپ سبھاپتی:** ڈیٹ از نوٹ دی ایشو۔۔مداخلت۔۔ڈیٹ از نوٹ دی ایشو۔ دیکھئے، آپ سے چاہتے ہیں اور کہتے کچھ ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، شاہد صدیقی صاحب۔

**شری ابو عاصم اعظمی:** سر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ میرا دکھ درد سمجھنے کی کوشش کیجئے۔

**شری اپ سبھاپتی:** آپ کا دکھ کچھ بھی ہوگا۔

**شری ابو عاصم اعظمی:** میں ہوم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں آتنک واد بڑھنے کے پیچھے یہ چیزیں بھی تو نہیں ہیں۔ اور جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اگر انہیں کورٹ کچہری میں جانے کو بھی نہیں ملے گا۔۔مداخلت۔۔

**شری اپ سبھاپتی:** آپ ختم کیجئے۔۔مداخلت۔۔ شاہد صدیقی صاحب، آپ بولئے ۔۔مداخلت۔۔

**شری ابو عاصم اعظمی:** اگر ان کی حفاظت نہیں ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آئی۔ایس۔آئی۔ یا لشکر طیبہ کے لوگوں کے کانٹیکٹ میں آ کر کے اس ماحول کو اور بڑھائیں۔ سر، میں ان باتوں کو جاننا چاہتا ہوں، مجھے ہوم منسٹر صاحب سے ان سب باتوں کا جواب چاہیئے۔ دھنیواد، شکریہ۔

"ختم شد"

**श्री शाहिद सिद्दिकी:** एक बात मैं बहुत साफ रूप से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के किसी भी दूसरे शहरी से ज्यादा हिन्दुस्तान का मुसलमान आतंकवाद से नफ़रत करता है और नफरत इसलिए करता है क्योंकि हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार मुसलमान ही है। जिसे आप लोग इस्लामिक आतंकवाद कहते हो, मुस्लिम आतंकवाद कहते हो, उससे अगर कोई लड़ेगा तो आपकी बंदूकें, आपका पोटा, आपका माकोका नहीं लड़ेगा, ये जो दुनिया के मुसलमान हैं, ये जो हिन्दुस्तान के मुसलमान हैं, यही आतंकवाद से लड़ेंगे। यह हमारी लड़ाई है।

**एक माननीय सदस्य:** ये तो हमारी तरफ इशारा करके कह रहे हैं।

**श्री उपसभापति:** वह मुसलमानों की बात कह रहे हैं, आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)... दोस्ती से कह रहे हैं...(**व्यवधान**)...

**श्री शाहिद सिद्दिकी:** सर, जब भी इस मुल्क में कोई आतंकवादी वाकया होता है, चाहे वह बनारस में हो, अयोध्या में हो, फैजाबाद में हो या लखनऊ में हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस समय हम लोग, हर मुसलमान अपने घर में बैठकर खौफ महसूस करता है। हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए खौफ महसूस करते हैं। ट्रेनों में सफर करते हुए हम अपने बच्चों से कहते हैं कि जो लिस्ट बाहर लगी हुई है रात को उसे निकाल देना, पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि हममें से हर आदमी को कटघरे में खड़ा करके रख दिया जाता है। जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो हर मुसलमान को, हमको टेलीविज़न के चैनल पर बुलाकर पूछा जाता है कि आप इसके खिलाफ क्यों नहीं बोले, जवाब दीजिए? हम बोलते हैं, हम जोर-जोर से बोलते हैं, पूरी ताकत से बोलते हैं, फिर भी हमसे कहा जाता है कि जवाब दीजिए।

सर, मेरे दिल में एक बात का बड़ा ज़ख्म है, हम पचास बार कह चुके हैं लेकिन हर बार वही असत्य गोएबल्स की तरह रिपीट किया जाता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। इसका जवाब हम कितनी बार देंगे? मुझे यह बताया जाए कि क्या महात्मा गांधी का क़ातिल मुसलमान था? मुझे बताया जाए कि क्या इंदिरा गांधी का क़ातिल मुसलमान था? मुझे बताया जाए कि क्या एलटीटीई के लोग मुसलमान हैं? मुझे बताया जाए कि क्या माओज़ मुसलमान हैं? मुझे बताया जाए कि क्या नक्सलाइट मुसलमान हैं? नॉर्थ-ईस्ट के अन्दर आज जितने उल्फा के आतंकवादी हैं, क्या वे मुसलमान हैं? यह कह देना कि नहीं, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम यह नहीं कहते कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, हम तो बस इतना कहते हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं। यह बात बड़े प्यार से हज़ार बार कही जाती है और यह कहकर हमारे मुंह पर थूका जाता है, सारे हिन्दुस्तान के मुसलमानों के मुंह पर थूका जाता है।

हिन्दुस्तान के मुसलमान को पूरा भरोसा है। इस देश के अन्दर गुजरात जैसे चाहे हज़ार कांड हो जाएं, लेकिन फिर भी हमारा भरोसा खत्म नहीं होगा। हम इस मुल्क के लिए जान देंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि चाहे हज़ार दंगे हो जाएं, हम इस मुल्क के लिए मरेंगे, मुल्क की मिट्टी को लेकर जाएंगे, क्योंकि आप इस बात को समझ लीजिए, मुसलमान इस बात को जानता है कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा मुल्क नहीं है, जहां मुसलमानों को हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने का अधिकार हो, जहां मुसलमानों को लोकतांत्रिक अधिकार हों, जो मेरे देश के अन्दर हैं, जो मेरे हिन्दुस्तान के अन्दर हैं। इस बात का अहसास मुसलमानों को पूरी तरफ से है, आप इस बात को समझिए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप आतंकवादियों के हमलों में मदद करते हैं और कैसे मदद करते हैं, ऐसे मदद करते हैं कि जब भी कहीं कोई वाक़या होता है, अभी धमाके की गूंज बाक़ी होती है कि हम कह देते हैं कि इसके पीछे कौन है, हम किसी न किसी का नाम ले लेते हैं, लेकिन, सर, ऐसे कितने केसिज़ सामने आए हैं, महाराष्ट्र में, आन्ध्र प्रदेश में, जिसमें यह बात गलत साबित हुई। हम लोग प्रधान मंत्री जी से जाकर मिले थे, हमने कहा था कि कितने बेगुनाह मारे जाते हैं, लेकिन उनके पुलिस अफसर क्या कहते हैं कि आपका दबाव होता है, मीडिया का दबाव होता है, हमारा दबाव होता है। उन पुलिस अफसरों की जान छुड़ाने के लिए दो-चार अंजान, गरीब, मजबूर और बेकस किस्म के लोगों को पकड़कर बंद कर देते हैं और कह देते हैं कि ये फलां हुजरी से हैं, फलां फुजरी से हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि कर लीजिए, यह भी कर लीजिए। अगर देश को फायदा होता है तो कुर्बान कर दीजिए, मगर इससे देश को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा कि आप असली आतंकवादियों को तो छोड़ देते हैं और खाना पूरी करने के लिए इन मासूम लोगों को पकड़ लेते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि असली आतंकवादी भाग जाते हैं, असली छूटे रहते हैं, असली हमला करते रहते हैं और आप एक झूठ बोलते हैं, जिसे छुपाने के लिए आपको सौ झूठ और बोलने पड़ते हैं। मुसलसल यही हो रहा है।

जब तक आप एक पॉलिसी नहीं बनाएंगे। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आप एक क्लीयर पॉलिसी बनाइए और इस चीज़ को डिफाइन कीजिए कि टैररिस्ट कौन हैं। क्या नक्सलाइट टैररिस्ट नहीं हैं? क्या माओइस्ट टैररिस्ट नहीं हैं? जो दंगा करते हैं और बेगुनाहों का कत्ल करते हैं, क्या वे टैररिस्ट नहीं हैं? क्या सिर्फ एक किस्म के लोग, एक कौम के लोग, एक मज़हब को मानने वाले लोग टैररिस्ट माने जाते हैं। जब तक आप टैररिज़्म को डिफाइन नहीं करेंगे, मामला हल नहीं होगा। इस तरह की बात होती रहेगी।

सर, जब से मैं यहाँ आया हूँ, पिछले पाँच सालों से यह बात कहना चाह रहा हूँ। आज मौका मिला है, इसलिए खुदा के लिए मुझे कहने दीजिए। मैं जानता हूँ कि इस हाउस का वक्त बड़ा कीमती है। यह मेरी आवाज़ नहीं है, यह हिन्दुस्तान के 15-16 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ हैं। इसलिए इस बात को कहने दीजिए।

सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस की बात आप करते हैं। इंटेलिजेंस के अन्दर मुसलमान बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। आप कैसे पेनेट्रेट करेंगे? आप टैररिस्ट्स से अपने पोटा से नहीं लड़ सकते। बॉर्डर के पार से जो टैररिस्ट्स भेजे जा रहे हैं, आपको उनके बीच पेनेट्रेट करना होगा। कौन पेनेट्रेट करेगा? पेनेट्रेट मैं करूँगा या मेरे बच्चे करेंगे, मेरे भाई करेंगे। उन्हें आप पुलिस में जगह देते हैं? आप मुसलमानों को इंटेलिजेंस में, रॉ के अन्दर आई०बी० के अन्दर, सी०आई०डी० के अन्दर जगह देते हैं? यह समझ लीजिए कि इस देश में जो सबसे बुरा डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटीज के ताल्लुक से, वह इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है और आज तक इसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं हुई। मैं होम मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस के अन्दर आपने माइनॉरिटीज़ को सही रिप्रिज़ेंटेशन देने के लिए क्या किया है, क्या कर रहे हैं? इसलिए मत दीजिए कि उन्हें कोई एहसान चाहिए, इसलिए दीजिए कि आपको टेररिज़्म से लड़ना है। अगर ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को लेकर चलिए, वरना यह नहीं होगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने फॉल्स एन्काउन्टर्स होते हैं-- हमारे सिस्टम की यह बुनियाद है कि हजार गुनाहगार बच जाएँ, लेकिन एक बेगुनाह को सजा न मिले। यह वह बुनियाद है, जिस पर यह पूरा लोकतंत्र, यह पार्लियामेंट, यह संविधान और हम यहाँ खड़े हुए हैं। अगर हम इसको खत्म कर देंगे, तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं उनसे भी दर्ख्वास्त करना चाहता हूँ , जो हमारे देश के वकील हैं। वकील के दिल में इस संविधान की बहुत इज्जत है। मैं उसी इज्जत को सामने रखते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के वकीलों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बदतरीन दुश्मन को इंसाफ का पूरा-पूरा हक देंगे और उन देशों को बता देंगे, जहाँ इंसाफ नहीं मिलता, जहाँ के शहरियों को आवाज़ उठाने की इजाजत नहीं मिलती। मुझे फख्र क्यों है, हिन्दुस्तान पर? मैं कहता हूँ कि मुझे हजार बार मौका मिले, तो मैं इस मिट्टी में पैदा होना चाहूँगा। क्यों? ...(**समय की घंटी**)... क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस मुल्क में मुझे इंसाफ मिलेगा। संविधान मुझे इंसाफ देता है ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** शाहिद साहब, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मगर वक्त का ख्याल रखिए।

**श्री शाहिद सिद्दिकी:** इसलिए वकील जो है, उसका पूरा-पूरा हक दें। वकील जो है, उसे क्या मालूम कि जो पकड़ा जा रहा है, उसमें कौन बेगुनाह है और अक्सर बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं। इसलिए उनको डिफेंड करने के लिए उनका वकील सामने आए। हम टैररिज्म से लड़ने के लिए इकट्ठे होकर, राजनीति से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ें।

मैं मिनिस्टर साहब से आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि आप इसके लिए कोई कमेटी बनाइए, ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाइए या आप दोनों सदनों में अलग-अलग कमेटी बनाइए, जिसमें मुख्तलिफ़ पार्टियों की नुमाइंदगी हो और जो बैठकर यह गौर करे कि टैररिज्म से लड़ने के लिए लाँग टर्म स्ट्रेटजी क्या होगी। सोशल फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर, पोलिटिकल फ्रंट पर, मीडिया के फ्रंट पर, प्रोपोगैंडा के फ्रंट पर, ये सारी चीजें हैं, जिन पर आपको लेना पड़ेगा। आज तक ईमानदारी से टैररिज्म से लड़ने की कोशिश नहीं हुई। हम ब्लेम गेम खेलते रहे। हम एक-दूसरे को निशानदेही करते रहे और टैररिस्ट्स को फायदा पहुँचाते रहे। इसके खिलाफ हमको एक पोलिटिकल विल की जरूरत है...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति:** आप प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए।

**श्री शाहिद सिद्दिकी:** पोलिटिकल विल किसी एक पार्टी की विल नहीं होती ...(**समय की घंटी**)... पोलिटिकल विल [illegible] [illegible] विल होती है। टोटल विल होती है, हमारी ज्वायंट विल होती है। इस विल को हमें पूरी ताकत से बताना [illegible] धन्यवाद।

**شری شاہد صدیقی ''اتر پردیش'' :** ایک بات میں بہت صاف روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے کسی بھی دوسرے شہری سے زیادہ ہندوستان کا مسلمان آتنک واد سے نفرت کرتا ہے اور نفرت اس لئے کرتا ہے کیوں کہ ہندوستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ آتنک واد کا سب سے بڑا شکار مسلمان ہی ہے۔ جسے آپ لوگ اسلامک آتنک واد کہتے ہو، مسلم آتنک واد کہتے ہو، اس سے اگر کوئی لڑے گا تو آپ کی بندوقیں، آپ کا پوٹا، آپ کا مکوکہ نہیں لڑے گا، یہ جو دنیا کے مسلمان ہیں، یہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں، یہی آتنک واد سے لڑیں گے، یہ ہماری لڑائی ہے۔

**ایک معزز ممبر:** یہ تو ہماری طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں۔

**شری اپ سبھاپتی:** وہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں۔۔مداخلت۔۔ دوستی سے کہہ رہے ہیں۔۔مداخلت۔۔

**شری شاہد صدیقی:** سر، جب بھی اس ملک میں کوئی آتنک وادی واقعہ ہوتا ہے، چاہے وہ بنارس میں ہو، ایودھیا میں ہو، فیض آباد میں ہو یا لکھنؤ میں ہو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ، ہر مسلمان اپنے گھر میں بیٹھ کر خوف محسوس کرتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں۔ ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے ہوئے ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ جولسٹ باہر لگی ہوئی ہے، رات کو اسے نکال دینا، پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیوں کہ ہم میں سے ہر آدمی کو کٹگھرے میں کھڑا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی آتنک وادی حملہ ہوتا ہے تو ہر مسلمان کو، ہم کو ٹیلی ویژن کے چینل پر بلا کر پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کے خلاف کیوں نہیں بولے، جواب دیجئے؟ ہم بولتے ہیں، ہم زور زور سے بولتے ہیں، پوری طاقت سے بولتے ہیں، پھر بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ جواب دیجئے۔

سر، میرے دل میں ایک بات کا بڑا زخم ہے، ہم پچاس بار کہہ چکے ہیں لیکن ہر بار وہی استیہ گوبھلس کی طرح رپیٹ کیا جاتا ہے کہ ہر مسلمان آتنک وادی نہیں ہوتا، لیکن آتنک وادی مسلمان ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہم کتنی بار دیں گے؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا مہاتما گاندھی کا قاتل مسلمان تھا؟ مجھے بتایا جائے کہ کیا اندرا گاندھی کا قاتل مسلمان تھا؟ مجھے بتایا جائے کہ کیا ایل۔ٹی۔ٹی۔ای۔ کے لوگ مسلمان ہیں؟ مجھے بتایا جائے کہ کیا ماؤز مسلمان ہیں؟ مجھے بتایا جائے کہ کیا نکسلائٹ مسلمان ہیں؟ ناردھ ایسٹ کے اندر آج جتنے الفا کے آتنک وادی ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ یہ کہہ دینا کہ نہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے مسلمان آتنک وادی ہیں، ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ سارے آتنک وادی مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں۔

†[]Transliteration in Urdu Script

یہ بات بڑے پیار سے ہزار بار کہی جاتی ہے اور یہ کہہ کر ہمارے منہ پر تھوکا جاتا ہے، سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے منہ پر تھوکا جاتا ہے۔

ہندوستان کے مسلمان کو پورا بھروسہ ہے۔ اس دیش کے اندر گجرات جیسے چاہے ہزار کانڈ ہو جائیں، لیکن پھر بھی ہمارا بھروسہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم اس ملک کے لئے جان دیں گے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے ہزار دنگے ہو جائیں، ہم اس ملک کے لئے مریں گے، ملک کی مٹی کو لیکر جائیں گے، کیوں کہ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی دوسرا ملک نہیں ہے، جہاں مسلمانوں کو حکومت بنانے اور بگاڑنے کا ادھیکار ہو، جہاں مسلمانوں کو لوک تانترک ادھیکار ہوں، جو میرے دیش کے اندر ہیں، جو میرے ہندوستان کے اندر ہیں۔ اس بات کا احساس مسلمانوں کو پوری طرح سے ہے۔ آپ اس بات کو سمجھئے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ آتنک وادیوں کے حملوں میں مدد کرتے ہیں اور کیسے مدد کرتے ہیں، ایسے مدد کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی واقع ہوتا ہے، ابھی دھماکے کی گونج باقی ہوتی ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ہم کسی نہ کسی کا نام لے لیتے ہیں۔ لیکن سر، ایسے کتنے کیسز سامنے آئے ہیں، مہاراشٹر میں، آندھرا پردیش میں، جس میں یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ ہم لوگ پردھان منتری جی سے جا کر ملے تھے، ہم نے کہا تھا کہ کتنے بے گناہ مارے جاتے ہیں، لیکن ان کے پولس افسر کیا کہتے ہیں کہ آپ کا دباؤ ہوتا ہے، میڈیا کا دباؤ ہوتا ہے، ہمارا دباؤ ہوتا ہے۔ ان پولس افسروں کی جان چھڑانے کے لئے دو چار انجان، غریب، مجبور اور بے کس قسم کے لوگوں کو پکڑ کر بند کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں اجمری سے ہیں، فلاں فجری سے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کہہ لیجئے، یہ بھی کر لیجئے۔ اگر دیش کو فائدہ ہوتا ہے تو قربان کر دیجئے، مگر اس سے دیش کو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا کہ آپ اصلی آتنک وادیوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور خانہ پری کرنے کے لئے ان معصوم لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصلی آتنک وادی بھاگ جاتے ہیں، اصلی چھوٹے رہتے ہیں، اصلی حملہ کرتے ہیں اور آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں، جسے چھپانے کے لئے آپ کو سو جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ مسلسل یہی ہو رہا ہے۔

جب تک آپ ایک پالیسی نہیں بنائیں گے۔ میں ہوم منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک کلیئر پالیسی بنایئے اور اس چیز کو ڈفائن کیجئے کہ ٹیررسٹ کون ہیں؟ کیا نکسلائٹ ٹیررسٹ نہیں ہیں؟ کیا ماؤسٹ ٹیررسٹ نہیں ہیں؟ جو دنگا کرتے ہیں اور بے گناہوں کا قتل کرتے ہیں، کیا وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں؟ کیا صرف ایک قسم کے لوگ، ایک قوم کے لوگ، ایک مذہب کو ماننے والے لوگ ٹیررسٹ مانے جاتے ہیں۔ جب تک آپ ٹیررزم کو ڈیفائن نہیں کریں گے، معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اس طرح کی بات ہوتی رہے گی۔

سر، جب سے میں یہاں آیا ہوں، پچھلے پانچ سالوں سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ آج موقع ملا ہے، اس لئے خدا کے لیے مجھے کہنے دیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ اس ہاؤس کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ یہ میری آواز نہیں ہے، یہ ہندستان کے ۱۶۔۱۵ کروڑ مسلمانوں کی آواز ہے۔ اس لئے اس بات کو کہنے دیجئے۔

سر، دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انٹیلی جینس کی بات آپ کرتے ہیں۔ انٹیلی جینس کے اندر مسلمان بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے۔ آپ کیسے پینیٹریٹ کریں گے؟ آپ ٹیررزم سے اپنے پوٹا سے نہیں لڑ سکتے۔ بارڈر کے پار سے جو ٹیررسٹ بھیجے جا رہے ہیں، آپ کو ان کے بیچ پینیٹریٹ کرنا ہوگا۔ کون پینیٹریٹ کریگا؟ پینیٹریٹ میں کرونگا یا میرے بچے کریں گے، میرے بھائی کریں گے۔ انہیں آپ پولیس میں جگہ دیتے ہیں؟ آپ مسلمانوں کو انٹیلی جینس میں، راء کے اندر، آئی بی کے اندر، سی آئی ڈی کے اندر جگہ دیتے ہیں؟ یہ سمجھ لیجئے کہ اس دیش میں جو سب سے برا ڈپارٹمنٹ ہے، مائنارٹیز کے تعلق سے، وہ انٹیلی جینس کا ڈپارٹمنٹ ہے اور آج تک اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ میں ہوم منسٹر صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ انٹیلی جینس کے اندر آپ نے مائنارٹیز کو صحیح ریپرزینٹیشن دینے کے لئے کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اس لئے مت دیجئے کہ انہیں کوئی احسان چاہئے، اس لئے دیجئے کہ آپ کو ٹیررزم سے لڑنا ہے۔ اگر ایمانداری سے لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کو لیکر چلئے، ورنا یہ نہیں ہوگا۔

تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے فالس ایکاؤنٹر ہوتے ہیں۔ ہمارے سسٹم کی یہ بنیاد ہے کہ ہزار گنہگار بچ جائیں، لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ ملے۔ یہ وہ بنیاد ہے، جس پر یہ پورا لوک تنتر، یہ پارلیمنٹ، یہ سمودھان اور ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کو ختم کر دیں گے، تو باقی کچھ نہیں بچے گا۔ اس لئے میں ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے دیش کے وکیل ہیں۔ وکیل کے دل میں اس سمودھان کی بہت عزت ہے۔ میں اسی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش کے وکیلوں کو اس بات پر دھیان دینا چاہئے کہ ہم اپنے بدترین دشمن کو انصاف کا پورا پورا حق دیں گے اور ان دیشوں کو بتا دیں گے، جہاں انصاف نہیں ملتا، جہاں کے شہریوں کو آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ملتی۔ مجھے فخر کیوں ہے، ہندستان پر؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے ہزار بار موقع ملے، تو میں اس مٹی میں پیدا ہونا چاہوں گا۔ کیوں؟.....(وقت کی گھنٹی).....کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ اس ملک میں مجھے انصاف ملے گا۔ سمودھان مجھے انصاف دیتا ہے .....مداخلت.....

**شری اُپ سبھاپتی:** شاہد صاحب، آپ بہت اچھا بول رہے ہیں، مگر وقت کا خیال رکھئے۔

**شری شاہد صدیقی :** اس لئے وکیل جو ہے، اس کا پورا پورا حق دیں۔ وکیل جو ہے، اسے کیا معلوم کہ جو پکڑا جا رہا ہے، اس میں کون بے گناہ ہے اور اکثر بے گناہ پکڑے جا رہے ہیں۔ اس لئے ان کو ڈفینڈ کرنے کے لئے ان کا وکیل سامنے آئے۔ ہم ٹیررزم سے لڑنے کے لئے اکٹھے ہو کر، راجنیتی سے اوپر اٹھکر لڑائی لڑیں۔

میں منسٹر صاحب سے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لئے کوئی کمیٹی بنایئے، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنایئے یا آپ دونوں سدنوں میں الگ الگ کمیٹی بنایئے، جس میں مختلف پارٹیوں کی نمائندگی ہو اور جو بیٹھ کر یہ غور کرے کہ ٹیررزم سے لڑنے کے لئے لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ سوشل فرنٹ پر اکانامک فرنٹ پر، پالیٹیکل فرنٹ پر، میڈیا کے فرنٹ پر، پروپگنڈے کے فرنٹ پر، یہ ساری چیزیں ہیں، جن پر آپ کو لینا پڑے گا۔ آج تک ایمانداری سے ٹیررزم سے لڑنے کی کوشش نہیں ہوئی ہے۔ ہم بلیم گیم کھیلتے رہے۔ ہم ایک دوسرے کو نشانہ ہی کرتے رہے اور ٹیررسٹ کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ اس کے خلاف ہم کو ایک پالیٹیکل ول کی ضرورت ہے... مداخلت...

**شری اُپ سبھاپتی:** آپ پلیز کنکلوڈ کیجئے۔

**شری شاہد صدیقی:** پالیٹکل ول کسی ایک پارٹی کی ول نہیں ہوتی۔ ....(وقت کی گھنٹی)..... پالیٹیکل ول اس سدن کی ول ہوتی ہے۔ ٹوٹل ول ہوتی ہے، ہماری جوائنٹ ول ہوتی ہے۔ اس ول کو ہمیں پوری طاقت سے بتانا پڑے گا۔ دھنیواد۔

"ختم شد"

**श्री हरेन्द्र सिंह मलिक** (हरियाणा): माननीय उपसभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और मृतकों तथा घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और आपसे एक अनुरोध भी करता हूँ कि ऐसी दुखद घटनाओं पर भविष्य में इस प्रकार की चर्चाओं को अनुमति न दें तो अच्छा होगा।

हम लोगों को बनारस, फैजाबाद और लखनऊ के ब्लास्टों को बधाई देनी चाहिए कि वहाँ जो आतंकवादी घटना हुई, उसे उन्होंने एक राष्ट्रीय हमला समझा, जबकि पार्लियामेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हिन्दू-पक्ष लेकर और एक मुस्लिम-पक्ष लेकर के खड़ा हो जाता है। राष्ट्र बचेगा तो हिन्दू और मुसलमान बचेंगे। अगर राष्ट्र नहीं बचा तो हिन्दू और मुसलमान क्या बचेंगे। जब आतंकवादी घटना होती है, जहाँ बम फटता है, तो वहाँ कोई यह नहीं देखता कि वहाँ मुसलमान बैठा है या हिन्दू बैठा है या इसाई बैठा है या कौन बैठा है। इस प्रकार मैं यह आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप हमारे संरक्षक हैं। मैं इस पीठ से निर्देश चाहता हूँ कि जो वक्ता यहां बोलें वह अपने आपको संविधान के दायरे में रखकर बोलें, किसी धर्म की या मजहब की बात कहकर न बोलें। आतंकवादी जो काम कर रहे हैं, उसी काम में हम जाने-अनजाने में उनकी मदद करते हैं। महोदय, आतंकवादी जब आतंकवाद फैलाता है, वह सरहद के पार से आया है, उसने आतंकवाद का विचार फैलाने के साथ चाहा है कि तेरे ऊपर एक कौम का, एक धर्म का आश्रित मिल जाये। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर इस मुल्क का 12-15 करोड़ मुसलमान आतंकवादी हो जाए तो मुल्क, मुल्क नहीं रहेगा, वह कब्रगाह में बदल जाएगा, लेकिन यह हो नहीं सकता और न है। सच्चाई तो यह है कि इस मुल्क का मुसलमान जिसको हम यहां आतंकवादी कहने का प्रयास कर रहे हैं, वह सब से ज्यादा गरीब है। उस बेचारे को दो जून की रोटी मुहैया नहीं हो रही है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस बात को देखें कि यह बार-बार क्यों होता है? हम चर्चा कर लेते हैं और आप 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की घोषणा कर देते हैं, लेकिन क्या जिस बाप का या जिस मां का बेटा चला गया, जिस बहन का भाई चला जाये, जिस बहन की मांग उजड़ गई हो तो उसको 10 लाख या 5 लाख देने से उसका आदमी मिल जाएगा? हम कारगर कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? महोदय, हमारा गोपनीय तंत्र है, हमारा जो सूचना तंत्र है, उसमें आपने किस कौम का आदमी भर्ती किया है, उस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह अपने कार्य के प्रति निष्क्रिय रहा तो आप उसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं करते, उसे दंड क्यों नहीं दिया जाता? एक चर्चा सी॰आई॰डी॰ की आई। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारी स्टेट की सी॰आई॰डी॰ कभी ऐसे सूचना-तंत्र का काम ही नहीं करती, वह तो लंबी विवेचनाओं को विवेचित करने का काम करती है। वह काम तो "एलआईयू" और "आईबी" करती है। महोदय, "आईबी"/"सीबी" केन्द्र के अधीन हैं। मैं मिश्र जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इन के कारखाने भी पुलिस ही है। हम केन्द्र को बुराई देकर नाहक परेशानी मोल लेते हैं। जो हमारी स्टेट की पुलिस है, वह रोज आतंकवादी पैदा करती है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। मैं फरनगर

का जिक्र करना चाहता हूं। हरसोली के एक गरीब मुसलमान के लड़के को, एक पैसे वाले ने नाम देकर, उसका नाम मोटरसाईकल चोरी में लिखवा दिया। यह अभी की घटना है। मनसूरपुर थाना दूसरा है, हरसोली का थाना शाहपुर है। फिर वे लोग डी०आई०जी० के पास गए, एस०पी० के पास गए, आई०जी० के पास गए। उसके बाद उनकी दोबारा जांच हुई और अब खतौली का सर्किल ऑफिसर जांच कर रहा है। उसके बाद मैंने अखबार में, सुबह जब मैं फरनगर से चला तो पढ़ा कि उनको इनाम घोषित कर दिया गया। एक गरीब किसान के बेटे का नाम लिखवा दिया केवल इसलिए कि वह मुसलमान था। आप देखें, आपकी पुलिस इस तरह इनाम घोषित कर रही है। ऐसे में वह क्या करेगा? वह कल किसी-न-किसी की शरण में जाएगा, भागेगा। फिर उसको धन्ना सेठ मिलता है जो बॉर्डर-पार से पैसा लाता है और वह उसको संरक्षण देता है। वह उसके लिए अच्छा वकील मुहैया कराएगा और वह उसके हाथ का खिलौना बनकर आतंकवादी का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह निर्देश होना चाहिए कि धर्म व जाति के नाम पर इस प्रकार का काम न हो।

मान्यवर, नौजवानों की बात कही गई, शायद मदनी साहब ने कही। मान्यवर, नौजवान कतई आतंकवादी नहीं हैं। मुल्क का हर बाशिंदा धर्म-प्रेमी है। धर्म को मानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हिंदू हूं, ऐसी ही सच्चाई यह है कि शाहिद सिद्दिकी भाई मुसलमान धर्म को मानने वाले हैं। महोदय, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि नौजवान के हाथ को काम चाहिए, उसे बंदूक नहीं चाहिए और आतंकवाद लाठी से नहीं सख्ती से मिटता है। जो लोग कहते हैं मरहम लगाकर आतंकवाद मिट जाएगा, उससे तो आतंकवाद नहीं मिटेगा। पंजाब इस बात का गवाह है। पंजाब में अगर पंजाब के नागरिक सहयोग नहीं करते और पंजाब में दृढ़ इच्छा-शक्ति वहां की सरकार नहीं दिखाती तो आतंकवाद वहां कभी खत्म नहीं होता। पंजाब का आतंकवाद केवल मरहम से खत्म नहीं हुआ, पंजाब का आतंकवाद वहां के बाशिंदों की दृढ़ इच्छा-शक्ति से, उनके देश के प्रति प्रेम और पुलिस की सख्त कार्यवाही से खत्म हुआ और उस में हम लोगों का भी रोल बनता है। माननीय गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं उससे इत्तफाक करता हूं। उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। अगर कहीं फोर्स सख्ती करता है तो मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जाति का है या मेरे धर्म का है। उस पर सख्ती करनी चाहिए, तब आतंकवाद खत्म हो जाएगा।

मैं एक और अनुरोध आपसे करना चाहता हूं मान्यवर कंधार की घटना चाहे ''रूबी'' का मामला हो। इन घटनाओं पर रोक होनी चाहिए। हमें इस बारे में यहां सख्त कानून बनाना होगा। माननीय गृह मंत्री जी को घोषणा करनी होगी कि भविष्य में किसी आतंकवादी को छोड़ने का काम नहीं किया जाएगा चाहे देश का कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो। अभी भी हमारी आंख नहीं खुली है। अभी अखबार में खबर छपी कि उत्तर प्रदेश में कुछ आतंकवादी पकड़े गए। वहां कहा गया कि वे राहुल गांधी को बंधक बनाकर उनके बदले में terrorists को छुड़ाना चाहते थे। हमें यह काम बंद करना पड़ेगा। अगर पूर्व में इस प्रकार की अदला-बदली नहीं होती तो ऐसी घटनाएं नहीं होतीं। मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम क्यो नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाते? जितने आतंकवादी इस मुल्क की जेलों में बंद हैं, चाहे वे उल्फा के हों, चाहे लिट्टे के हों, चाहे मार्क्सवादी हों या किसी जाति या किसी धर्म या किसी संगठन के हों, उनके लिए तीन महीने का समय तय कर दीजिए, कानून के मुताबिक उनको पूरा मौका दीजिए और इन तीन महीनों के अंदर फास्ट ट्रैक के जरिए फैसला करा दीजिए। अगर वे निर्दोष हों, तो उनको छोड़िए और अगर वे दोषी हों, तो उनको सजा दीजिए। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं, ताकि यह मुल्क अमन का मुल्क बन सके।

मान्यवर, आज भी हमें फख्र के साथ कहना चाहिए कि इस मुल्क में धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि संविधान के नाम पर लोगों का समर्पण है और जो लोग हिन्दू, मुसलमान की बात करते हैं, उनको यह सोचना होगा कि यह मुल्क हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब से मिलकर बना है। हमारे संविधान में, हमारे आइन में अलगाव की कहीं गुंजाइश नहीं है। एक बात में शाहिद साहब से कहना चाहता हूं कि शरीयत के मुताबिक हमको कयामत में आने का एक बार ही मौका मिला है, बार-बार जन्म लेने का सौभाग्य आप न देखें। इसी के साथ, मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

**श्री उपसभापति:** श्री बशिष्ठ नारायण सिंह। आप दो-तीन मिनट में बहुत संक्षेप में बोल दीजिए। आप अच्छा बोलते हैं, मगर समय कम है, कम समय में बोलिए।

**श्री बशिष्ठ नारायण सिंह** (बिहार): उपसभापति महोदय, इस सदन में आतंकवाद पर बार बार चर्चा होती रही है और इसमें दो राये कभी नहीं रही हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष में जो भी लोग बैठे रहे हों, सबने एकमत से एक स्वर में ऐसी घटनाओं की निंदा की है। आज के इस नए समय में गंभीर रूप से कुछ बातों पर हमें विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद का एंगिल बदल रहा है। संसद के परिसर में आतंकवाद का हमला होता है, मुंबई जो कॉमर्शियल सिटी है वहां आतंकवाद का हमला होता है और इस बार कोर्ट परिसर में आतंकवाद का हमला हुआ है। भारत की कॉमर्शियल सिटी पर हमला, भारत के सर्वोच्च संसद पर हमला और भारत के मुख्य स्तंभ न्यायपालिका पर हमला, वैसे आतंकवाद के हमले तो कई जगहों पर हुए हैं, असम में तो मजदूरों पर भी हमला हो रहा है और कश्मीर, बोर्डर

पर भी हमला हो रहा है। निंदा का प्रस्ताव तो अब तक होता रहा है, मगर लगता है कि इस बार सदन इस सवाल पर ठीक से बहस नहीं कर पाएगा, न्याय नहीं कर पाएगा। अब तो जरूरी है कि एक बार इस सदन से ऐसा संकल्प हो, जिससे यह जाहिर हो कि निंदा प्रस्ताव करने का मौका शायद ही सदन के सामने फिर उपस्थित हो।

उपसभापति महोदय, आज की बहस में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार के एजेण्डा पर प्रमुखता के रूप में आतंकवाद एक बिन्दु हो या नहीं है। भारत सरकार राज्य सरकारों को इस बात के लिए सहमत कराए कि जो आज का मुख्य एजेंडा है, कानून व्यवस्था का और आतंकवाद का, इसको सर्वोपरि स्थान पर रखे, तभी इसका मुकाबला हम कर सकते हैं। हमको लगता है कि विचार के स्तर पर जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, उनके लिए आपको अलग तरह से स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, जो आतंकवादी संघीय ढांचे को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं उनके लिए दूसरी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, जो आर्थिक आतंकवाद फैलाकर अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी और जहां राज्य की व्यवस्था में अपनी अलग पहचान, अपना अलग शासन चलाने की पद्धति यानी पेरलल गवर्नमेंट चलाने की जिनकी योजना है, उनके लिए अलग से कार्यक्रम तैयार करना पड़ेगा, अलग से स्कीम्स तैयार करनी पड़ेंगी। हमारे जो बोर्डर स्टेट्स हैं, जहां पर आतंकवाद की समस्या गंभीर बन चुकी है, जहां घुसपैठ ओर दूसरी तरह ही समस्याएं आ रही हैं, उनके लिए दूसरी तरह की स्ट्रेटजी अपनानी की जरूरत पड़ेगी। सरकार का एक बात पर साफ बयान देने की जरूरत है कि अभी तक जो उपाय हमने किए हैं, वे उपाय आज तक सार्थक सिद्ध नहीं हुए हैं, चाहे वे हमारे कानून हों, चाहे हमारी टेकनीक हों, चाहे जो मैथड्स हों, जो तरीके हों, चाहे हमारी खुफिया विभाग की एजेन्सी हों, चाहे समन्वित रूप से राज्यों और केन्द्र सरकार की पुलिस से संबंधित हो, आधुनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, या सूचना तंत्र हो। उपसभापति महोदय, कभी-कभी चर्चा हो जाती है तो दिमान में बहुत तनाव पैदा हो जाता है कि धर्म के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, कभी जाति के साथ इस समस्या को जोड़ दिया जाता है। भारत में रहने वाले किसी भी जाति के लाखों लोग कभी साम्प्रदायिक और आतंकवादी नहीं हो सकते। आतंकवादी तो छोटे समूहों के लोग रहते हैं और छोटे समूहों के लोग से किसी बड़े ऐंगल में इस बात को जोड़ देने से लोकतंत्र को बड़ा खतरा होगा।

उपसभापति महोदय, अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात से समाप्त करूंगा कि आज से कुछ ही दिन पहले लोकतंत्र और रिलीजन पर एक बड़ा ही सार्थक भाषण मैं सुन रहा था गांधी शाति प्रतिष्ठान में प्रो॰ एस॰ रिंपोंचे ने दिल्ली में बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि रिलीजन और धर्म की व्याख्या ही हमारे लोगों ने डिफरेंट ढंग से करनी शुरू कर दी है। लोकतंत्र भी जीवन पद्धति है और रिलीजन भी व्यक्ति को स्वयं को कंडक्ट करने का अपने तरीके से सबसे बड़ा माध्यम है। जो सच्चा धार्मिक होगा, वह कभी लोकतंत्र का विरोधी नहीं हो सकता और जो लोकतांत्रिक व्यक्ति होगा, वह कभी धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मुझको यह बात अच्छी लगी।

मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि आज इस देश में और खासकर इस घटना के बाद सरकार को यह घोषित करना चाहिए कि पांच-छः महीने के अंदर हमारी नई स्ट्रेटजी यह होगी, हमारी नई तरकीब यह होगी, हम राज्य सरकारों से लेकर सभी जगहों पर अपनी एजेंसियों को इस नए आधुनिक तरीके से सुसज्जित करने का काम करेंगे, चाहे वह विचार के आधार पर हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो। एक बार ऐसी क्यों नहीं घोषणा होती है, शांति मार्च न केवल पार्टियों के लोग करें, बल्कि भिन्न-भिन्न रिलीजन के लोग, भिन्न-भिन्न स्वयं सेवी संगठनों के लोग और दूसरे लोग भी इस ढंग का पीस मार्च करें, इससे देश में अमन-चैन का माहौल पैदा होगा, नहीं तो बड़ी खतरनाक स्थिति होगी, कहीं मजदूर पर आतंक होगा तो कहीं किसी और पर होगा। इस पर विचार करने की जरूरत है।

इतना ही कहकर, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि केवल यही घोषणा करना सरकार के लिए पर्याप्त नहीं है कि मुआवजा कितना दे दिया, सरकार के लिए यही घोषणा करने की जरूरत नहीं है कि अपने राज्यों को क्या निर्देश दिया है, सरकार के लिए घोषणा करने की जरूरत है कि राज्य के साथ आपका समन्वय, सम्पर्क और नए तरीके के प्रभावी कदम क्या हैं और यही आपको करना चाहिए। जय हिन्द।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Home Minister has to again go to Lok Sabha for replying to the Resolution. Now we will end this here.

SHRI DINESH TRIVEDI (West Bengal): Sir, I promise you I will not cross my limit. I understand the importance of time. I will just start and finish in two minutes. I do not want to get into the formalities of anything. The House has condemned it, therefore, I am not going to do it individually. Today it reminds me of Lal Bahadur Shastri. His slogan was 'Jai Jawan Jai Kisan'. Jawan is because of the security. Today when I read the statement it says that we will see to it that there is communal harmny. I do not even feel liking asking clarifications because we never get the answers. Today it sounds more like a party manifesto

than the will of the Government—'Bland statement, bland statement, bland statement'. I would like to congratulate the people of this country. If today there is harmony, it is not because of the Government or because of us. At times people say, "In spite of us", I would just like to say that there is something called accountability.

सर, घर में यदि हम दरबान रखते हैं तो उसका दायित्व बनता है कि हमारे सेफ्टी-सिक्युरिटी रहे। यदि सरकार है तो उसका दायित्व बनता है और कहीं न कहीं एकाउंटेब्लिटी आती है।

सर, मैं जानता हूं कि समय नहीं है, इसलिए मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि श्री राम जेठमलानी जी ने बड़ी अच्छी बात कही और दूसरे लोगों ने भी कहा कि We penetrate the criminal organisation. I want to tell you and everybody knows, that it is the criminal organisation which has penetrated us, including this Parliament. I am not saying that. It is the Vohra Committee Report which says so. I have to go to the Supreme Court. I would like know from the hon. Minister as to what they have done on the recommendation of the Vohra Committee. Government after Government came. The NDA also was there. But they also did not do anything. What have you done? I have written letters, but there was no response. Very casually, you come here and say, "Maoist is there." But you cannot substantiate. And, as rightly said by the hon. Member, Shahidji, even those guys, who are not criminals, you are forcing to take up that. Here, my dear friend, Yechuryji said, 'Islamic fundamentalists', and today, he says that we should not use such words. Sir, I want to speak a lot, but as I have promised, I will not take much time. I want to know what the accountability of the Government is. Can they say: "Yes; this is it. We are not going to see this day again."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The reply will be at 6 O' clock. Now, the hon. Minister to move the Resolution.

---

## GOVERNMENT RESOLUTION

### Proclamation issued by President on 20th November, 2007, under Article 356 of Constitution in relation to State of Karnataka

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, I rise to move:

> "That this House approves the Proclamation issued by the President on the 20th November, 2007, under Article 356 of the Constitution in relation to the State of Karnataka."

As the hon. Members are aware, election to constitute the Legislative Assembly of Karnataka was held in April, 2004. The election resulted in a hung Legislative Assembly in the State. On 28th May, 2004, a coalition Government, comprising Janata Dal (S) and the Congress (I) was formed. However, in January, 2006, a group of 39 MLAs of JD (S) led by Shri H.D. Kumaraswamy broke away form the alliance and formed a Government, with the support of BJP, with Shri H.D. Kumaraswamy as the Chief Minister. There was an understanding betwen the two coalition partners that the JD (S) would hold the Chief Minister's post for the first 20 months and the BJP for the next 20 months. The period of 20 months for the JD (S) ended on 3rd October, 2007. Seventy-nine MLAs of BJP presented before the Governor and withdrew the support to the coalition Government on 6th October, 2007. On 8th October, 2007, the leaders of the Congress (I) party also submitted a memorandum to the Governor stating that the Ministry headed by Shri H.D. Kumaraswamy had been reduced to a minortiy and demanded the dismissal of the Government. Thereafter, the Chief Minister met the Governor and submitted his resignation on 8th October, 2007. The Governor, in his Report, dated 8th October, 2007, recommended invoking the President's rule in the State of Karnataka as there was no possibility of any party or person being in a position to form a Ministry with a majority support in the Assembly. The Report of the Governor was considered by the Union Government and the President's rule was proclaimed on 9th October, 2007 in the State of Karnataka under article 356 (1) of the Constitution keeping the Legislative